गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 268
दि. 30.01.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

नम आंखों से 'दादा' को अंतिम विदाई, शोक में डूबा बारामती

(जीएनएस)। बारामती के लिए वह सुबह किसी भी आम सुबह जैसी नहीं थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, गलियों में भीड़ थी, लेकिन आवाज़ें नहीं थीं। हर चेहरे पर शोक, हर आंख में नमी और हर दिल में एक ही सवाल—क्या वाकई 'दादा' अब लौटकर नहीं आएंगे? जब उपमुख्यमंत्री अजित पवार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव काटेवाड़ी लाया गया, तो पूरा इलाका मानो ठहर गया। आसपास के गांवों, कस्बों और शहरों से लोग बिना किसी बुलावे के उमड़ पड़े। किसी के हाथ में फूल थे, किसी की आंखों में आंसू, तो कोई बस चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। यह दृश्य किसी राजनीतिक नेता का नहीं, बल्कि परिवार के एक मजबूत स्तंभ को खो देने का था।

सुबह होते ही काटेवाड़ी की ओर जाने वाले रास्तों पर लोगों की कतारें लग गईं। बुजुर्ग लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहे थे, महिलाएं सिसकियां दबाने की कोशिश कर रही थीं और युवा अपनी आंखें पोंछते हुए आगे बढ़ रहे थे। घर के बाहर अंतिम दर्शन के लिए लंबी लाइनें थीं। जैसे ही पार्थिव शरीर को रखा गया, वहां मौजूद कई लोग खुद को संभाल नहीं पाए। कुछ महिलाएं रोते-रोते जमीन पर बैठ गईं, कई लोग हाथ जोड़कर मौन प्रार्थना में डूब गए। बीच-बीच में "अजित दादा अमर रहें" और "अजित दादा परत या" के नारे गूंजते, लेकिन उनमें उत्साह नहीं, बल्कि टूटे दिलों की वेदना साफ झलकती थी।

अंतिम दर्शन के बाद जब पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया, तो बारामती की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। फूलों से सजा शव वाहन जैसे ही आगे बढ़ा, पूरा शहर ठहर सा गया। सड़क के दोनों ओर हजारों लोग खड़े थे। कई लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए थे, ताकि आखिरी बार दादा का दीदार कर सकें। दुकानों के शटर आधे गिरे थे, ट्रैफिक थम चुका था और हर निगाह उसी एक वाहन पर टिकी थी। यह सिर्फ़ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि जनता और उनके नेता के बीच बने उस गहरे रिश्ते की आखिरी झलक थी, जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है।

अंतिम यात्रा बारामती के उन्हीं इलाकों से होकर गुजरी, जहां अजित पवार ने दशकों तक राजनीति की, जनता से संवाद किया

और विकास की नींव रखी। हर मोड़ पर फूलों की बारिश हुई, कहीं मौन श्रद्धांजलि दी गई, तो कहीं लोग फूट-फूटकर रो पड़े। समर्थकों का कहना था कि अजित पवार सिर्फ़ नेता नहीं थे, बल्कि हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने वाले अपने आदमी थे। यही वजह थी कि उनकी विदाई में राजनीति की सीमाएं टूटती नजर आईं।

इस दुखद घड़ी में पवार परिवार का दर्द सबसे ज्यादा छलक रहा था। बेटे पार्थ और जय अपने पिता के पार्थिव शरीर के पास खड़े थे। दोनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब अंतिम संस्कार का समय आया, तो दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर पिता को मुखाग्नि दी। उस पल वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से गोलियों की सलामी दी गई, शोक का बिगुल बजा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार पंचतत्व में विलीन हो गए।

इस पूरे समय सुप्रिया सुले का रूप हर किसी को भीतर तक छू गया। राजनीतिक मतभेदों से परे, वह एक मजबूत सहारा बनकर परिवार के साथ खड़ी रहीं। अस्पताल से लेकर अंतिम संस्कार तक उन्होंने सुनेत्रा पवार का हाथ थामे रखा। पति को अचानक खोने के सदमे से टूट चुकी सुनेत्रा पवार को संभालते हुए सुप्रिया कई बार खुद भी फूट-फूटकर रो पड़ीं। उन्होंने पार्थ को गले लगाया, जय के सिर पर हाथ रखकर उसे ढांढस बंधाया। यह दृश्य राजनीति का नहीं, बल्कि एक भारतीय परिवार के गहरे मानवीय रिश्तों का था, जिसने हर देखने वाले की आंखें नम कर दीं।

अजित पवार को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए राजनीति, सिनेमा और सामाजिक जगत की कई बड़ी हस्तियां बारामती पहुंचीं। हर किसी की जुबान पर यही बात थी कि महाराष्ट्र ने एक मजबूत, जमीनी और विकास को प्राथमिकता देने वाले नेता को खो दिया है। दिन ढलने के साथ भीड़ धीरे-धीरे छंट गई, लेकिन बारामती की फिज़ाओं में सन्नाटा और दिलों में भारीपन बना रहा। लोग जानते थे कि समय आगे बढ़ेगा, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन 'दादा' की वह मौजूदगी, उनका अंदाज़ और जनता से उनका रिश्ता अब सिर्फ़ यादों में रह जाएगा। नम आंखों से दी गई यह विदाई इस बात की गवाह बनी कि अजित पवार सिर्फ़ सत्ता का नाम नहीं थे, बल्कि लोगों के दिलों में बसने वाली एक पहचान थे, जो बरसों तक जिंदा रहेगी।

पंजाब में समानता के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की बड़ी पहल, जालंधर में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र

(जीएनएस)। जालंधर। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम उठाया है। करीब छह सौ वर्ष पहले संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास द्वारा दिए गए मानवता, समानता और सामाजिक न्याय के विचारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए जालंधर जिले में डेरा बल्लां के निकट श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना को न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश में एक अनूठी पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो सामाजिक चेतना और समावेशी सोच को मजबूती देने का काम करेगी।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और विचारधारा को विश्व स्तर पर फैलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह अध्ययन केंद्र केवल एक भवन या संस्थान नहीं होगा, बल्कि यह समानता, बंधुत्व और सामाजिक सौहार्द के मूल्यों का जीवंत केंद्र बनेगा। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से जालंधर जिले में 9 एकड़ से अधिक भूमि इस अध्ययन केंद्र के नाम दर्ज की है।

वित्त मंत्री ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए

कुल तीन रजिस्ट्रियां पूरी की गई हैं। इनमें गांव नौगजा की रजिस्ट्री, जिसका क्षेत्रफल 64 कनाल 5 मरले है और जिसकी लागत 5 करोड़ 40 लाख 98 हजार 500 रुपये है, शामिल है। इसके अलावा गांव फरीदपुर में दो रजिस्ट्रियां की गई हैं, जिनमें पहली रजिस्ट्री 2 कनाल भूमि की है, जिसकी लागत 16 लाख 74 हजार रुपये रही, जबकि दूसरी रजिस्ट्री 10 कनाल 14 मरले भूमि की है, जिस पर 1 करोड़ 44 लाख 62 हजार 150 रुपये खर्च हुए हैं। इस तरह कुल 76 कनाल 19 मरले भूमि इस अध्ययन केंद्र के लिए ली गई है, जिसकी कुल लागत 7 करोड़ 2 लाख 54 हजार 659 रुपये बताई गई है।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह अध्ययन केंद्र आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी ज्ञान का एक मजबूत प्रकाश स्तंभ बनेगा। इसका मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को श्री गुरु रविदास जी के जीवन, संघर्ष और विचारों से परिचित कराना है, ताकि वे सामाजिक भेदभाव, ऊंच-नीच और असमानता के खिलाफ जागरूक हो सकें। उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास जी ने अपने समय में ही जाति, वर्ग और आर्थिक भेदभाव को नकारते हुए एक ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। आज के दौर में उनके विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं।

वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र का उद्देश्य केवल अकादमिक शोध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक जीवंत सामाजिक मंच के रूप में काम करेगा। यहां सेमिनारों, शोध कार्यक्रमों, प्रकाशनों और समुदाय-आधारित गतिविधियों के माध्यम से श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का संरक्षण, अध्ययन और प्रचार किया जाएगा। देश-विदेश के विद्वानों, सामाजिक चिंतकों और शोधकर्ताओं को इस केंद्र से जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि गुरु रविदास जी के विचारों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके।

सरकार का मानना है कि इस तरह की पहल से समाज में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समझने और उन्हें दूर करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा सकेंगे।

एग्रीस्टैक को लेकर बिहार सरकार का बड़ा एक्शन, मिशन मोड में फार्मर रजिस्ट्री, लक्ष्य पूरा करने वाले जिलों को मिलेगा इनाम

(जीएनएस)। पटना। बिहार में किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा, पारदर्शी और समयबद्ध लाभ दिलाने की दिशा में राज्य सरकार ने एग्रीस्टैक परियोजना को मिशन मोड में आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसी क्रम में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एग्रीस्टैक की प्रगति को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अब तक किए गए कार्यों, उपलब्धियों और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में साफ संकेत दिया गया कि आने वाले दिनों में इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें ढिलाई बरतने वाले जिलों से जवाबदेही भी तय की जाएगी। बैठक के दौरान विस्तृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया गया कि 2 फरवरी से 6 फरवरी तक पूरे राज्य में मिशन मोड में फार्मर रजिस्ट्री का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसानों को इस डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जा सके, ताकि भविष्य में योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी रुकावट के किसानों तक पहुंचे। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों को संबोधित करते

हुए कहा कि एग्रीस्टैक केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाला माध्यम है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी अधिकारियों को राज्य हित को सर्वोपरि रखते हुए समन्वय के साथ काम करना होगा।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि एग्रीस्टैक के कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि बिहार जल्द से जल्द इस परियोजना के दूसरे चरण में प्रवेश कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदर्शन के आधार पर जिलों को प्रोत्साहित करेगी। जो जिले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किसानों का 50 प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री लक्ष्य पूरा करेंगे, उन्हें सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं, जिन जिलों के लिए 35 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वे इसे पूरा करने पर 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि के पात्र होंगे। इस फैसले से जिलों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

बैठक में एक अहम फैसला यह भी लिया गया कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसानों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने साफ निर्देश दिया कि पूर्व में कॉमन सर्विस सेंटर और वसुधा केंद्रों के माध्यम से लिए जाने वाले 15 रुपये के सेवा शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब इस शुल्क का वहन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा, जिससे किसानों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी स्तर पर यह महसूस नहीं होना चाहिए कि सरकारी प्रक्रिया उनके लिए खर्चीली या जटिल है।

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों में से कम से कम 50 प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तय समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करें। जिन जिलों में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति पहले से संतोषजनक है, वहां और बेहतर प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह काम केवल आंकड़े पूरे करने के लिए नहीं, बल्कि किसानों के हित में स्थायी व्यवस्था खड़ी करने के लिए है। बैठक में कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने बताया कि राज्य के प्रत्येक रैयत किसान की फार्मर आईडी तैयार करना अनिवार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फार्मर आईडी के जरिए किसानों की पहचान, उनकी भूमि, फसलों और योजनाओं से जुड़ा पूरा डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी, बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को लाभ समय पर मिल सकेगा। उन्होंने इसे बिहार के कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया।

इस बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि 28 जनवरी को नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में बिहार सरकार के एग्रीस्टैक और फार्मर रजिस्ट्री कार्यों की विशेष सराहना की गई है। कार्यशाला में मुख्य सचिव के नेतृत्व में बिहार में मिशन मोड में किए जा रहे सुव्यवस्थित और प्रभावी कार्य को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे अन्य राज्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। यह बिहार के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। मुख्य सचिव ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की विशेष रूप से प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी। जिन जिलों का नाम सराहनीय कार्यों के लिए सामने आया, उनमें वैशाली, शिवहर, बेगूसराय, बक्सर, शेखपुरा और कटिहार प्रमुख हैं।

न्याय की चौखट पर ठहरा यूजीसी का नया नियम, सुप्रीम 'ब्रेक' ने खोले बड़े सवाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सवाल सिर्फ जीत या हार का नहीं है, न ही इसे किसी एक वर्ग की सफलता या सरकार के लिए झटके के रूप में देखा जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक दरअसल देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा एक गहरा संदेश है। पिछले कई दिनों से जिस मुद्दे पर देश के अलग-अलग शहरों में विरोध, बहस और असंतोष देखने को मिल रहा था, उस पर शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप यह बताता है कि मामला केवल नीतिगत बदलाव का नहीं, बल्कि समाज की दिशा तय करने वाला है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यूजीसी के 13 जनवरी को अधिसूचित नए नियमों पर फिलहाल फुल स्टॉप लगा दिया। अदालत ने साफ कहा कि इन नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है और यदि समय रहते इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया तो इसके "खतरनाक परिणाम" हो सकते हैं। कोर्ट की यह टिप्पणी अपने-आप में बेहद गंभीर है, क्योंकि इसमें केवल कानूनी खामियों की बात नहीं, बल्कि सामाजिक विभाजन की आशंका भी झलकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर शिक्षा संस्थानों में ही भेद और अलगाव की भावना पैदा होगी तो समाज में एकता कैसे बनी रहेगी। अदालत ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एक समय अश्वेत और श्वेत छात्रों के लिए अलग-अलग स्कूल हुआ करते थे और भारत को ऐसी स्थिति की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि देश की एकता हमारे स्कूलों और कॉलेजों के कैंपस में दिखनी चाहिए, न कि वहां से विभाजन की रेखाएं खिंचनी चाहिए।

न्यायालय ने यह भी माना कि संविधान राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, लेकिन किसी भी कानून या नियम में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यूजीसी के नए नियमों को लेकर अदालत की सबसे बड़ी आपत्ति यही रही कि जाति से जुड़े प्रावधान अस्पष्ट हैं और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसी वजह से कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इन नियमों को दोबारा ड्राफ्ट किया जाए और इसके लिए प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, न्यायविदों और सोशल इंजीनियर्स की एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाए, जो इन प्रावधानों की गहन जांच करे। इस आदेश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी और तब तक देशभर में 2012 के यूजीसी नियम ही लागू रहेंगे। यही वह बिंदु है, जिसे सामान्य वर्ग के एक बड़े हिस्से ने अपनी जीत के रूप में देखा है। बीते दिनों सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे छात्रों और अभिभावकों का कहना था कि नए नियम उनके साथ भेदभाव करते हैं और समान अवसर के अधिकार का हनन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोक ने उनके गुस्से और आशंकाओं को एक तरह से वैधानिक मान्यता दी है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामला किसी एक वर्ग के पक्ष या विपक्ष में फैसला सुनाने का नहीं है। असली चिंता यह है कि 75 साल बाद, जब देश जाति-विहीन समाज की ओर बढ़ने का दावा करता है, क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि आरक्षित वर्गों के भीतर भी अब अमीर-गरीब का अंतर उभर चुका है और समुदायों को छोटे-छोटे समूहों में बांट दिया गया है। ऐसे में नियम बनाते समय यह देखना जरूरी है कि जिन लोगों को वास्तव में सुरक्षा और समर्थन की जरूरत है, उन्हें वह मिले, लेकिन इसके नाम पर समाज में नई खाई न बने।

यूजीसी के नए नियमों के विरोध में दायर याचिकाओं में इन्हें सामान्य वर्ग के खिलाफ और भेदभावपूर्ण बताया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये नियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में समानता के सिद्धांत को कमजोर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को गंभीरता से लिया और कहा कि कानून की भाषा जितनी स्पष्ट होगी, उसका प्रभाव उतना ही न्यायसंगत होगा।

अब सवाल उठता है कि जिस 2012 के नियम को कोर्ट ने फिलहाल लागू रखने का आदेश दिया है, वह क्या कहता है। वर्ष 2012 में यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने और भेदभाव रोकने के लिए नियम बनाए थे। ये नियम जाति, धर्म, लिंग और भाषा सहित सभी प्रकार के भेदभाव पर लागू होते थे। इसके तहत हर संस्थान में 'इक्वल ऑपर्च्युनिटी सेल' और 'एंटी-डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर' की नियुक्ति का प्रावधान था। किसी भी छात्र या उसके अभिभावक को भेदभाव की शिकायत होने पर लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार था और संस्थान को 60 दिनों के भीतर उस पर फैसला करना होता था। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर छात्र, शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाती थी। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि 2012 के नियमों में कार्रवाई की बजाय सुझाव का भाव ज्यादा था और यही वजह रही कि समय-समय पर इन्हें और सख्त बनाने की मांग उठती रही। रोहित वेमुला और पायल तडवी के मामलों के बाद उनके परिजनों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार से नए नियम बनाने को कहा गया। लेकिन जब यूजीसी का नया नियम सामने आया, तो उसमें संतुलन की कमी और सामान्य वर्ग के प्रति भेदभाव का आरोप लगने लगा। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस मुद्दे पर सामने आई हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि यदि यूजीसी नए नियम लागू करने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में ले लेती और जांच समितियों में अपर कास्ट समाज को भी उचित प्रतिनिधित्व देती, तो सामाजिक तनाव की स्थिति नहीं बनती।

अजित पवार: आरोपों से ऊपर उठे राजनीति के 'दादा-पुरुष'

संपादकीय

दुखद हादसा

बुधवार सुबह बारामती के पास हुई एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार व चालक दल के सदस्यों समेत पांच लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। मुंबई से बारामती आ रहा चार्टर विमान मौसम की खराबी के कारण रनवे के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के कारणों का असली पता जांच के बाद ही चलेगा, मगर प्रथम दृष्टया धुंध के कारण दृश्यता में कमी ही बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में छह बार उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार के राज्य में राजनीतिक योगदान को नकारा नहीं जा सकता। राज्य में तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य विपक्षी दलों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। हालांकि, ममता बनर्जी ने उनकी मौत को लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु व चाचा शरद पवार ने उनकी मृत्यु को लेकर राजनीतिक बयानबाजी को खारिज किया है। निश्चय ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता अजित पवार की असामयिक दुर्घटना में मृत्य ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक शून्य जरूर पैदा कर दिया है। वहीं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के मुताबिक दुर्घटना क्रैश लैंडिंग के दौरान हुई। रनवे के निकट हुए हादसे में विमान में आग लग गई और स्थानीय लोगों के प्रयासों के बावजूद किसी को बचाया नहीं जा सका। विमान लियरजेट-45 सोलह साल पुराना था। घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। निस्संदेह, अजित पवार जनता के नेता थे और जमीनी स्तर पर लोगों से उनका गहरा जुड़ाव था। बताया जाता है कि प्रशासनिक मामलों में उनकी समझ गहरी थी। वे वंचित वर्ग को सशक्त करने के प्रयासों के लिये जाने जाते रहे हैं।

बहरहाल, अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में उनके बदलते दांव-पेचों के लिये याद किया जाता रहेगा। उनके बारे में कहा जाता रहा है कि वे उस कहावत को हकीकत बनाते रहे हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और ना ही स्थायी दुश्मन। वे अपनों के साथ तो रहे, गैरों को भी रास आए। उन्होंने चाचा और अपने राजनीतिक गुरु शरद पवार से राजनीति के गुर सीखे। शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता रहा है, लेकिन अजित पवार ने उनसे अलग होकर अपनी नई राह भी बनायी। यूं तो उन्होंने चाचा शरद के साथ राजनीतिक पारी शुरू की लेकिन साल 2023 आने तक वे एकला चलो की राजनीति करने लगे। हालांकि, उन्होंने चाचा शरद पवार की छत्रछाया में राजनीति का ककहरा सीखा लेकिन एक समय वे पार्टी का सिंबल भी ले जाने में कामयाब रहे। फिर शरद पवार को नई पार्टी बनाकर उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी। बारहवीं तक पढ़ाई के बावजूद वे अनुभवी नीतिकारों की सहायता से एक बेहतर प्रशासक भी साबित हुए। सहकारी चीनी मिलों से राजनीति की शुरुआत करने वाले पवार विधायक से लेकर सांसद तक चुने जाते रहे। वे राज्य में छह बार उप मुख्यमंत्री बने। साल 1991 में पहली बार बारामती से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने, लेकिन चाचा शरद पवार के लिये बाद में सीट खाली भी की। वे सबसे पहले 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। उनकी लोकप्रियता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि वे सात बार विधायक चुने गए। फिर वे विलासराव देशमुख की कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार में पहली बार सिंचाई मंत्री बने। फिर ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे। बाद में वे एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन में जल संसाधन मंत्री भी रहे। साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उनके अचानक भाजपा गठबंधन के साथ आने और उप मुख्यमंत्री बनने ने सबको चौंकाया था। फिर पवार साल 2023 में महायुति गठबंधन का हिस्सा बनकर पांचवीं बार उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि, एनसीपी में विभाजन के बाद शरद पवार परिवार से संबंध बनाये रखे। इसके बावजूद कि उन्होंने एनसीपी का नाम और सिंबल तक ले लिया था। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार को कई मायनों में हमेशा याद किया जाएगा।

> "अजित पवार का जीवन किसी राजसी विरासत की सहज कहानी नहीं था। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देओली प्रवरा क्षेत्र में जन्मे अजित पवार ने जीवन को बहुत करीब से संघर्ष करते हुए देखा। उनके पिता अनंतराव पवार फिल्म जगत से जुड़े रहे, राजकमल स्टूडियो में काम किया, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां साधारण रहीं।

यह खबर केवल एक व्यक्ति के निधन की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक पूरे युग के अचानक थम जाने की सूचना है। 28 जनवरी 2026 की सुबह जब बारामती में हुए विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार के असामयिक निधन की पुष्टि हुई, तो वह क्षण केवल पवार परिवार के लिए नहीं, बल्कि समूचे महाराष्ट्र और देश की राजनीति के लिए गहरे शोक और स्तब्धता का कारण बन गया। जिस नेता को लोग अधिकार, अनुभव और निर्णय क्षमता का पर्याय मानते थे, उसका इस तरह अचानक चले जाना सत्ता, प्रशासन और राजनीतिक संतुलन में एक बड़ा रिक्त स्थान छोड़ गया है। एक संभावनाओं भरी महाराष्ट्र की राजनीति एवं राष्ट्रीय विचारों का सफर ठहर गया, उनका निधन न केवल महाराष्ट्र के लिये, भारत की राष्ट्रवादी सोच के लिये बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रवादी राजनीति पर एक गहरा आघात है, अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से सहकारी आन्दोलन को भी गहरा धक्का लगा है।अजित पवार का जीवन किसी राजसी विरासत की सहज कहानी नहीं था। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देओली प्रवरा क्षेत्र में जन्मे अजित पवार ने जीवन को बहुत करीब से संघर्ष करते हुए देखा। उनके पिता अनंतराव पवार फिल्म जगत से जुड़े रहे, राजकमल स्टूडियो में काम किया, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां साधारण रहीं। औपचारिक शिक्षा माध्यमिक स्तर तक ही सीमित रही, किंतु जीवन की व्यावहारिक पाठशाला ने उन्हें वह सिखाया जो बड़े-बड़े शैक्षणिक संस्थान भी नहीं सिखा पाते। शायद यही कारण रहा कि अजित पवार की राजनीति किताबों से नहीं, जमीन से निकली हुई राजनीति थी, जिसमें किसानों की पीड़ा, सहकारी संस्थाओं की ताकत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नब्ज साफ दिखाई देती थी। राजनीति में उनका प्रवेश किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि सहकारी आंदोलन

की प्रयोगशाला से हुआ। 1982 में मात्र बीस वर्ष की आयु में उन्होंने एक चीनी सहकारी संस्था का चुनाव लड़ा। यह वही दौर था जब महाराष्ट्र की राजनीति में सहकारी संस्थाएं सत्ता की रीढ़ मानी जाती थीं। अजित पवार ने बहुत जल्दी समझ लिया कि यदि ग्रामीण महाराष्ट्र को साधना है तो उसे बैंक, चीनी मिल, सिंचाई और बिजली से जोड़ना होगा। यही समझ आगे चलकर उनकी राजनीतिक पहचान की सबसे बड़ी ताकत बनी।

1991 अजित पवार के राजनीतिक जीवन का निर्णायक वर्ष रहा। पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनने के साथ ही उन्होंने वित्तीय प्रशासन और संगठन संचालन में अपनी दक्षता का परिचय दिया। सोलह वर्षों तक इस पद पर बने रहना अपने आप में उनकी विश्वसनीयता और पकड़ को दर्शाता है। उसी वर्ष बारामती से लोकसभा के लिए निर्वाचित होना उनके बढ़ते कद का प्रमाण था, लेकिन उन्होंने यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी। यह फैसला केवल पारिवारिक निष्ठा का नहीं, बल्कि राजनीतिक दूरदृष्टि का भी उदाहरण था। इसके बाद विधानसभा में प्रवेश और फिर लगातार बारामती से जीत ने उन्हें जनाधार का वह आधार दिया, जिसे महाराष्ट्र की राजनीति में विरले ही कोई चुनौती दे सका। अजित पवार को सत्ता के गलियारों में पहुंचाने वाली सबसे बड़ी विशेषता उनकी प्रशासनिक पकड़ थी। कृषि, बागवानी, बिजली और जल संसाधन जैसे कठिन और संवेदनशील विभागों को संभालते हुए उन्होंने विकास और विवाद दोनों को नजदीक से जिया। जल संसाधन मंत्री के रूप में कृष्णा घाटी और कोकण सिंचाई परियोजनाओं से उनका नाम जुड़ा। इन परियोजनाओं ने जहां किसानों के लिए पानी और उम्मीद का संदेश दिया, वहीं आलोचनाओं और आरोपों का बोझ भी उनके कंधों पर रखा। इसके बावजूद वे उन नेताओं में रहे जो फाइलों से नहीं, फैसलों से पहचाने जाते थे।

उपमुख्यमंत्री के रूप में उनका सफर महाराष्ट्र की राजनीति में एक अनोखा अध्याय है। छह बार इस पद तक पहुंचना केवल राजनीतिक संयोग नहीं था, बल्कि सत्ता संतुलन, गठबंधन राजनीति और संगठनात्मक ताकत का परिणाम था। वे सरकार में अक्सर संकटमोचक की भूमिका में दिखे। बजट, वित्तीय प्रबंधन और संसदीय रणनीति में उनकी पकड़ ऐसी थी कि विरोधी भी उनके अनुभव को नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। उन्हें महत्वाकांक्षी कहा गया, कभी-कभी कठोर और रूखे स्वभाव का नेता भी बताया गया, लेकिन यह भी सच है कि सत्ता की वास्तविकता को वे भावनाओं से नहीं, निर्णयों से देखते थे। विवाद उनके राजनीतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे। सिंचाई घोटाले से लेकर बयानबाजी तक, कई मौके ऐसे आए जब उनकी छवि पर प्रश्नचिह्न लगे। "अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करके भरें?" जैसे बयान ने उन्हें आलोचनाओं के केंद्र में ला खड़ा किया। उन्होंने माफी भी मांगी, सफाई भी दी और समय के साथ उन विवादों से उबरते हुए फिर सत्ता के शीर्ष पर लौटे। यह उनकी राजनीतिक जिजीविषा का प्रमाण था कि आलोचना और आरोप उन्हें रोक नहीं पाए।

शरद पवार के साथ उनके रिश्ते को लेकर भी हमेशा चर्चाएं रहीं। कभी मतभेद, कभी दूरी और कभी सियासी अलग राह की अटकलें। लेकिन अजित पवार स्वयं को हमेशा शरद पवार का अनुयायी बताते रहे। उन्हें मिला "दादा" का संबोधन केवल पारिवारिक नहीं था, बल्कि वह एक राजनीतिक ब्रांड बन चुका था, जो उनके समर्थकों में भरोसे और नेतृत्व की भावना जगाता था। वे संगठनकर्ता भी थे और प्रशासक भी, रणनीतिकार भी और जमीनी नेता भी। उन्हें अपनी विविध आयामी भूमिकाओं से अपने को मिले 'दादा' के अलंकरण को सार्थक भी किया और जीवंतता भी दी। उनका असामयिक निधन एक क्रूर विडंबना है। जिस नेता ने दशकों तक सत्ता की उड़ान भरी, उसकी जीवन यात्रा एक विमान हादसे में थम गई। कहा जाता है कि दुर्घटना से कुछ समय पहले तक वे पूरी तरह सक्रिय थे, योजनाओं, बैठकों और राजनीतिक समीकरणों में व्यस्त। यह अचानक आई मृत्यु उस अनिश्चितता को रेखांकित करती है, जो सत्ता और जीवन दोनों के साथ जुड़ी है।

अजित पवार का व्यक्तित्व एवं कृतित्व सफल राजनेता, समाज निर्माता, ग्राम-उद्धारक, सहकारी आन्दोलन पुरोधा, कुशल प्रशासक के रूप में अनेक छवि, अनेक रंग, अनेक रूप में उभरकर सामने आता हैं। आपके जीवन की दिशाएं विविध एवं बहुआयामी थीं। आपके जीवन की धारा एक दिशा में प्रवाहित नहीं हुई, बल्कि जीवन की विविध दिशाओं का स्पर्श किया। यही कारण है कि कोई भी महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आपके जीवन से अछूता रहा हो, संभव नहीं लगता। आपके जीवन की खिड़कियाँ समाज एवं राष्ट्र को नई दृष्टि देने के लिए सदैव खुली रही। उनकी सहजता और सरलता में गोता लगाने से ज्ञात होता है कि वे राजनीतिक सरोकार से ओतप्रोत एक अल्हड़ एवं साहसिक व्यक्तित्व थे। बेशक अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन अपने जुझारु राजनीति जीवन के दम पर वे हमेशा भारतीय राजनीति एवं राष्ट्रवादी सोच के आसमान में एक सितारे की तरह टिमटिमाते रहेंगे।

आज जब महाराष्ट्र और देश उनके निधन पर शोकाकुल है, तब अजित पवार का मूल्यांकन केवल प्रशंसा या आलोचना के तराजू पर नहीं किया जा सकता। वे विवादों से घिरे रहे, लेकिन उनसे परिभाषित नहीं हुए। उनकी राजनीति कठोर थी, लेकिन उसमें अनुभव की गहराई थी। वे लोकप्रियता से अधिक प्रभाव में विश्वास रखते थे। शायद यही कारण है कि उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा सन्नाटा है, जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। अजित पवार का जीवन यह सिखाता है कि राजनीति केवल भाषणों और नारों से नहीं चलती, बल्कि निर्णय, जोखिम और जिम्मेदारी से चलती है। उनका जाना एक चेतावनी भी है और एक स्मृति भी, क्योंकि सत्ता क्षणभंगुर है, लेकिन अनुभव और प्रभाव लंबे समय तक याद किए जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में "दादा" के नाम से पहचाना जाने वाला यह व्यक्तित्व अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसकी छाया आने वाले वर्षों तक राज्य की राजनीति पर बनी रहेगी।

प्रेरणा

समय की कसौटी पर तपती सफलता

एक युवक था, जो बाहर से शांत दिखता था लेकिन भीतर बेचैनी से भरा हुआ था। उसकी परेशानी यह नहीं थी कि वह असफल है, बल्कि यह थी कि उसकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती थी। वह रोज़ खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता, फिर भी उसे लगता कि दुनिया उसे नज़रअंदाज़ कर रही है। लोग उससे आगे निकल रहे थे, तारीफ़ें बटोर रहे थे, पहचान पा रहे थे और वह वहीं खड़ा महसूस करता था। इसी उलझन को लेकर वह एक दिन एक शांत स्थान पर पहुँचा, जहाँ एक वृद्ध संत रहते थे। उसने अपनी बात सीधे शब्दों में रख दी—मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन मेरी प्रगति दिखाई क्यों नहीं देती?

संत ने उसकी बात सुनी, लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने युवक को साथ चलने को कहा। वे दोनों एक खुले मैदान में पहुँचे, जहाँ अलग-अलग आकार के पेड़ खड़े थे। कुछ छोटे थे, कुछ बहुत ऊँचे और कुछ ऐसे भी थे जो बाहर से साधारण लगते थे, लेकिन उनकी छाया सबसे ठंडी थी। संत ने कहा—इन पेड़ों को देखो। क्या सभी एक साथ बड़े हुए हैं? क्या सभी ने एक ही समय में फल दिए? युवक ने ध्यान से देखा और पहली बार महसूस किया कि वह हमेशा ऊँचाई देखता आया था, जड़ों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया।

संत ने ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और बोले—यही वह जगह है जहाँ असली काम होता है। ऊपर दिखने वाली हर मजबूती की कहानी नीचे छुपी होती है। जो लोग जल्दी दिखने लगते हैं, वे अक्सर भीतर से तैयार नहीं होते। और जो भीतर से तैयार होते हैं, वे दिखने की जल्दी नहीं करते। यह बात सुनकर युवक के मन में जैसे कोई गांठ खुलने लगी। संत ने कहा कि आज की दुनिया ने एक भ्रम पैदा कर दिया है—अगर तुम दिख रहे हो, तो तुम सफल हो। लेकिन यह भ्रम बहुत महँगा पड़ता है। दिखना और बनना दो अलग बातें हैं। दिखना बाहर की स्वीकृति है, बनना भीतर की प्रक्रिया। जो इंसान बनने की प्रक्रिया को अधूरा छोड़कर दिखने के पीछे भागता है, वह थोड़ी दूर तक तो चमकता है, लेकिन ठहर नहीं पाता।

युवक को एहसास हुआ कि उसकी बेचैनी का कारण उसकी मेहनत नहीं, उसकी तुलना थी। वह दूसरों की घड़ी देखकर अपनी घड़ी चलाना चाहता था। संत बोले—समय सबका एक जैसा नहीं होता। किसी का सूरज जल्दी निकलता है, किसी का देर से। लेकिन देर से निकलने वाला सूरज भी उतना ही उजाला देता है। समस्या तब होती है जब इंसान अपने समय से लड़ने लगता है। संत ने धैर्य को समझाते हुए कहा कि धैर्य का मतलब इंतज़ार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है बिना परिणाम देखे लगातार सही दिशा में चलना। यह वह शक्ति है जो इंसान को टूटने नहीं देती, जब आसपास सब कुछ जल्दी में बिखर रहा होता है। जल्दबाज़ी में मिली सफलता अक्सर इंसान को अहंकारी बना देती है और अहंकार सबसे तेज़ गिरने का रास्ता है।

उन्होंने उदाहरण दिया कि कच्चा फल जल्दी तोड़ लिया जाए तो दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन स्वाद नहीं देता। पका हुआ फल देर से मिलता है, लेकिन उसकी मिठास याद रहती है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जो लोग धैर्य से अपने कौशल को निखारते हैं, अपने चरित्र को मज़बूत करते हैं, वे देर से पहचाने जाते हैं, लेकिन गहराई से पहचाने जाते हैं।

युवक ने पूछा—तो क्या मुझे बस इंतज़ार करना चाहिए? संत मुस्कुराए और बोले—नहीं, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन बेचैनी के बिना। तुम्हें खुद को हर दिन बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन दुनिया के फैसले की चिंता किए बिना। जब तुम खुद से संतुष्ट हो जाओगे, तब दुनिया की स्वीकृति तुम्हारे लिए अनिवार्य नहीं रहेगी। और अक्सर उसी पल दुनिया तुम्हारी ओर देखना शुरू कर देती है।

संत ने यह भी कहा कि आज की पीढ़ी जल्दी थक जाती है, क्योंकि वह जल्दी नतीजे चाहती है। जब नतीजे नहीं मिलते, तो आत्म-संदेह शुरू हो जाता है। इंसान सोचने लगता है कि शायद वह गलत है। जबकि सच यह है कि बहुत सी चीज़ें समय लेती हैं। चरित्र, समझ, कौशल और स्थिरता—ये सब धीरे-धीरे बनते हैं। जो जल्दी बनता है, वह जल्दी टूटता है।

युवक को अपनी ज़िंदगी के कई दृश्य याद आने लगे। कितनी बार उसने बीच रास्ते में ही खुद पर शक किया था, कितनी बार उसने अपनी दिशा बदल ली थी, सिर्फ इसलिए कि किसी और को जल्दी सफलता मिल गई थी। संत बोले—जो बार-बार दिशा बदलता है, वह मंज़िल से नहीं, खुद से दूर हो जाता है। स्थिर रहना सबसे कठिन कला है और सबसे ज़रूरी भी।

संत ने अंत में कहा—समय एक शिक्षक है। वह सबको सिखाता है, लेकिन सब्र वालों को ही पूरा पाठ समझ में आता है। जो समय से लड़ता है, वह थक जाता है। जो समय के साथ चलता है, वह मजबूत हो जाता है। अगर आज तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, तो इसे व्यर्थ मत समझो। यह वह दौर है जब तुम गढ़े जा रहे हो।

युवक के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दिया। उसे कोई त्वरित समाधान नहीं मिला था, लेकिन उसे एक स्थायी समझ मिल गई थी। वह जान गया था कि सफलता कोई दौड़ नहीं, एक यात्रा है। और इस यात्रा में धैर्य सबसे भरोसेमंद साथी है।

वह वहाँ से लौटा, लेकिन अब उसकी चाल में हड़बड़ी नहीं थी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए। उसे अब जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसे यह विश्वास हो गया था कि जो सच में तैयार होता है, उसे देर से सही, लेकिन मजबूती से पहचान मिलती है। और यही पहचान समय की कसौटी पर टिकती है।

लाभकारी टिकाऊ बिजनेस मॉडल की ओर बढ़ता रुझान

साल 2025 स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ, जहां केवल तेज़ ग्रोथ के बजाय टिकाऊ बिज़नेस मॉडल, मुनाफ़े और सामाजिक प्रभाव पर भी जोर दिया जाने लगा। अब स्टार्टअप्स को सफलता के लिए दीर्घकालिक स्थिरता और सामाजिक योगदान की कसौटी पर भी परखा जाने लगा है। पिछले एक दशक की तुलना में 2025 को 'संयम और परिपक्वता' का वर्ष कहा जा सकता है-जहां दुनिया भर में स्टार्टअप्स की संख्या भले ही तेज़ी से न बढ़ी हो, लेकिन जो स्टार्टअप टिके, वे अधिक मज़बूत और व्यावहारिक साबित हुए।

वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप गतिविधियां अधिक यथार्थवादी रहीं। दुनियाभर में हजारों नए स्टार्टअप सामने आए, लेकिन निवेशकों और बाज़ार का रुख साफ़ था- अब केवल 'आइडिया' नहीं, बल्कि रेवेन्यू, कैश फ्लो और स्पष्ट बिज़नेस मॉडल मायने रखते हैं। कोरोना काल के बाद स्टार्टअप्स में निवेश एक तरह की दौड़ बन गया था, वहीं 2025 में फंडिंग अपेक्षाकृत चयनात्मक रही। अमेरिका, यूरोप और एशिया में बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स ने खुद को पुनर्गठित किया, कई का विलय हुआ और कुछ बाज़ार से बाहर भी हो गए। वैश्विक स्तर पर अनुमान लगाया जाता है कि 2025 में लाखों नए स्टार्टअप पंजीकृत हुए, लेकिन उनमें से एक सीमित प्रतिशत ही वास्तव में 'सफल' कहलाने योग्य रहे-यानी जिन्होंने स्थिर राजस्व, विस्तार या लाभप्रदता की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए। वर्ष 2025 में सफलता की परिभाषा बदल गई। पहले जहां यूनिकॉर्न बनना ही सफलता का प्रतीक माना जाता था, वहीं अब सस्टेनेबल ग्रोथ, मुनाफ़ा और दीर्घकालिक टिकाव को अधिक महत्व दिया जाने लगा। टेक्नोलॉजी, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, हेल्थटेक, क्लाइमेट टेक, फिनटेक और डीप-टेक जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया। इसके विपरीत, केवल उपभोक्ता छूट और तेज़ विस्तार पर आधारित कई मॉडल कसौटी पर खरे नहीं उतरे। भारत 2025 में भी दुनिया के सबसे सक्रिय स्टार्टअप देशों में शामिल रहा। देश में लगभग 22,000 से अधिक नए स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए- जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है और उद्यमशीलता की गति स्पष्ट करता है। हालांकि, बीता वर्ष भारत के लिए भी 'छंटाई' का वर्ष रहा- स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी, लेकिन गुणवत्ता व फोकस में सुधार दिखा। कई स्टार्टअप्स ने आक्रामक विस्तार के बजाय लागत नियंत्रण, स्थानीय बाज़ार और मुनाफ़े पर ध्यान दिया। साल 2025 में भारत के स्टार्टअप परिदृश्य में एक सीमित हिस्सा ही बड़े पैमाने पर सफल हुआ। कुछ स्टार्टअप्स ने मुनाफ़े की दिशा में कदम बढ़ाए , कई का विलय या अधिग्रहण हुआ और कुछ बाज़ार की वास्तविकताओं के सामने टिक नहीं पाए। यह स्थिति नकारात्मक नहीं, बल्कि स्वस्थ इकोसिस्टम का संकेत है, जहां अव्यावहारिक मॉडल खुद ही बाहर हो जाते हैं।

2025 में वैश्विक स्टार्टअप परिदृश्य में भारत की स्थिति तीसरे या चौथे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में बनी रही। अमेरिका और चीन के बाद भारत को अक्सर यूरोप के साथ तुलना में रखा जाने लगा। भारत ने लगभग 125 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बनाए (स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से अधिक है)। इनमें से कई ने इस वर्ष यह मुकाम हासिल किया और ग्रोथ जारी रखी। भारत की खासियत रही कि वह केवल उपभोक्ता बाज़ार नहीं, बल्कि नवाचार और स्केल- दोनों का केंद्र बन रहा है। भारतीय स्टार्टअप्स अब केवल घरेलू नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को भी लक्ष्य बना रहे हैं। हालांकि, पूंजी की उपलब्धता, गहन तकनीकी अनुसंधान और वैश्विक ब्रांड निर्माण के मामले में भारत अभी विकसित देशों से पीछे है। 2025 में स्टार्टअप निवेशकों का व्यवहार बदला हुआ दिखा। 'ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट' की जगह 'सस्टेनेबल रिटर्न' निवेश का मंत्र बना। भारत में शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को अपेक्षाकृत समर्थन मिला, लेकिन बड़े फंडिंग राउंड्स की संख्या सीमित रही। इससे स्टार्टअप्स को अपने खर्च और रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा। भारत में तकनीकी स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग माहौल चुनौतीपूर्ण रहा। कुल इक्विटी फंडिंग पिछले साल के मुकाबले लगभग $10.5 बिलियन तक गिर गई। यह संकेत है कि निवेशक अब और अधिक सावधानी से धन लगा रहे हैं और केवल 'स्पष्ट प्रगति वाला मॉडल' ही पूंजी आकर्षित कर पा रहा है। 2025 ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के सामने कई संरचनात्मक चुनौतियां हैं। वैश्विक अनिश्चितता का सीधा असर भारतीय स्टार्टअप फंडिंग पर पड़ता है। मसलन भारत में अब भी उपभोक्ता-आधारित स्टार्टअप्स की संख्या अधिक है, जबकि गहरे तकनीकी नवाचार की कमी महसूस की जाती है। टैक्स, अनुपालन और राज्यों के बीच अलग-अलग नियम कई स्टार्टअप्स के लिए बाधा बनते हैं। उच्च स्तरीय तकनीकी और प्रबंधन प्रतिभा की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उपलब्धता सीमित है। साल 2025 स्टार्टअप की दुनिया में उत्साह से अधिक विवेक का वर्ष रहा। स्पष्ट हुआ कि स्टार्टअप्स का भविष्य केवल बड़ी वैल्यूएशन में नहीं, बल्कि समस्या समाधान, टिकाऊ बिज़नेस और सामाजिक प्रभाव में निहित है। भारत ने 2025 में साबित किया कि उसका स्टार्टअप इकोसिस्टम अब किशोरावस्था से निकलकर परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन दिशा स्पष्ट है। यदि भारत पूंजी, नीति और कौशल के मोर्चे पर संतुलन बना पाया, तो कुछेक वर्षों में वह वैश्विक स्टार्टअप दुनिया में बड़ा खिलाड़ी बनने के साथ ही दिशा देने वाला देश भी बन सकता है।

अभियान

उग्र शक्ति की गोद में करुणा का रहस्य

कालीघाट मंदिर तक की यात्रा किसी पर्वतारोहण या तपस्वी वन-यात्रा जैसी नहीं है। यह यात्रा कोलकाता की सांसों के बीच से होकर गुजरती है—जहां ट्राम की घंटी, रिक्शों की चरमराहट, दुकानों की पुकार, फूलों की खुशबू और लोगों की भीड़ एक साथ बहती है। यह मंदिर शहर से बाहर नहीं, शहर के भीतर है; यूं कहें कि कोलकाता की धड़कनों के बीच बैठा हुआ। शायद यही कारण है कि कालीघाट केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जीवन का जीवंत प्रतीक बन जाता है। यहां पहुंचते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि मां काली एकांत की देवी नहीं हैं। वे उस शक्ति का नाम हैं जो जीवन के शोर, अव्यवस्था और संघर्ष के बीच भी सक्रिय रहती है। कालीघाट की गलियों में प्रवेश करते ही एक अजीब-सी बेचैनी घेर लेती है। जगह तंग है, लोग अधीर हैं, पंडों की आवाजें तेज़ हैं और हर कोई जल्दी में है। कोई फूल बेच रहा है, कोई प्रसाद, कोई आपको पकड़कर 'शीघ्र दर्शन' का प्रस्ताव दे रहा है। पहली नज़र में यह सब आध्यात्मिकता के विपरीत लग सकता है, लेकिन यही इस मंदिर की पहली परीक्षा है। यहां आने वाला श्रद्धालु अगर शांति की तलाश में है, तो उसे पहले अपने भीतर के भ्रम से टकराना होगा। कालीघाट यह नहीं कहता कि आस्था हमेशा शांत, सुसंस्कृत और सौम्य होती है। यह मंदिर बताता है कि आस्था कई बार असुविधाजनक भी होती है। जैसे-जैसे गर्भगृह नजदीक आता है, बाहर की अराजकता भीतर किसी और ही रूप में बदलने लगती है। शोर कम नहीं होता, लेकिन उसका असर बदल जाता है। अचानक ऐसा लगता है मानो यह सब किसी बड़े सत्य की भूमिका हो। दर्शन का क्षण बहुत छोटा होता है। कोई लंबा ठहराव नहीं, कोई विस्तार से पूजा नहीं। बस एक झलक—और वही झलक भीतर कुछ खोल देती है। मां काली की बड़ी आंखें सीधे देखती हैं, जैसे बिना किसी भूमिका के, बिना किसी औपचारिकता के। यह दृष्टि डराती नहीं, बल्कि पकड़ लेती है। यहां डर इसलिए नहीं होता कि देवी उग्र हैं, बल्कि इसलिए कि वे बनावटी आवरण को भेद देती हैं।

पुराणों के अनुसार कालीघाट वह स्थान है जहां देवी सती के दाएं पैर की चार अंगुलियां गिरी थीं। इसलिए यहां देवी की पूर्ण मूर्ति नहीं, बल्कि पवित्र पदचिह्न की पूजा होती है। यह तथ्य जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा भी है। कालीघाट पूर्णता का नहीं, अपूर्णता की स्वीकृति का प्रतीक है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि शक्ति हमेशा संपूर्ण, सुसज्जित और आदर्श रूप में ही प्रकट हो—यह आवश्यक नहीं। कभी-कभी अवशेष ही सबसे अधिक ऊर्जावान होते हैं। शायद इसलिए कालीघाट की शक्ति मूर्ति में नहीं, अनुभव में बसती है।

मां काली का स्वरूप पहली बार देखने वाले को विचलित कर सकता है। काला रंग, बाहर निकली जीभ, मुंडमाला और उग्र नेत्र—यह सब भय का प्रतीक नहीं, बल्कि सत्य का अनावरण है। उनकी जीभ बाहर इसलिए नहीं कि वे क्रोधित हैं, बल्कि इसलिए कि अहंकार के क्षण में उन्होंने स्वयं को पहचान लिया। शिव को अपने चरणों तले देखकर उन्हें बोध हुआ और वही बोध लज्जा बनकर प्रकट हुआ। यह दृश्य बताता है कि सबसे उग्र शक्ति भी आत्मबोध के सामने झुक जाती है। यहां करुणा मुस्कान में नहीं, स्वीकार में प्रकट होती है।

कालीघाट उन गिने-चुने शक्तिपीठों में है जहां पशु-बलि की परंपरा का इतिहास रहा है। आधुनिक दृष्टि से यह विषय असहज हो सकता है, लेकिन कालीघाट इस असहजता से भागता नहीं। यह मंदिर सरल उत्तर नहीं देता। यहां बलि को उत्सव नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व के रूप में देखा गया। समय के साथ यह परंपरा प्रतीकात्मक हो गई है, लेकिन प्रश्न आज भी जीवित है। कालीघाट यह सिखाता है कि शक्ति की उपासना आसान नहीं होती। इसमें अपने भीतर के हिंसक, लालची और अंधे पक्षों से भी सामना करना पड़ता है।

कालीघाट का नाम आते ही रामकृष्ण परमहंस की स्मृति अपने-आप जाग उठती है। उनके बिना इस मंदिर की आत्मा को समझना अधूरा है। रामकृष्ण ने यहां काली को भयावह देवी नहीं, सजीव मां के रूप में देखा। उनके लिए काली कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थीं, बल्कि चेतना थीं—जो हंसती हैं, रूठती हैं, दुलार करती हैं और साधक से संवाद करती हैं। उन्होंने तंत्र की उग्र छवि को प्रेम और भक्ति में बदल दिया। कालीघाट उनके लिए साधना का स्थल नहीं, घर था। एक ऐसा घर जहां मां हर रूप में स्वीकार्य थीं।

यहां धर्म और जीवन की व्यवहारिक सच्चाइयां साथ-साथ चलती हैं। पंडा-प्रथा, दान-दक्षिणा, व्यापार, राजनीति—सब कुछ यहां मौजूद है। कई लोग इसे देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन कालीघाट शायद यही कहना चाहता है कि जीवन भी ऐसा ही है। यहां पवित्रता और स्वार्थ एक-दूसरे से अलग नहीं। कालीघाट आदर्शों का नहीं, यथार्थ का मंदिर है। मां काली यहां किसी को प्रमाणपत्र नहीं देतीं। वे यह नहीं पूछतीं कि कौन कितना योग्य है। वे सबको स्वीकार करती हैं—शायद इसलिए क्योंकि वे भीतर के सत्य को देखती हैं, बाहरी आवरण को नहीं।

कालीघाट में स्त्री-शक्ति किसी गुप्त गुफा में नहीं, बल्कि सड़क पर प्रकट होती है। यह शक्ति भीड़ में है, शोर में है, संघर्ष में है। यह मंदिर बताता है कि स्त्री-शक्ति को केवल कोमल, सौम्य और सजावटी रूप में पूजना आसान है, लेकिन उसे उग्र, असुविधाजनक और स्वतंत्र रूप में स्वीकार करना साहस मांगता है। कालीघाट उसी साहस की परीक्षा है। यहां दर्शन कुछ ही क्षण का होता है, लेकिन वही क्षण जीवन भर के लिए पर्याप्त हो सकता है।

आज कालीघाट एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। राजनीतिक हस्तियां आती हैं, सुधार की योजनाएं बनती हैं, व्यवस्थाएं बदली जाती हैं। लेकिन इन सबके बावजूद मंदिर की आत्मा जस की तस बनी हुई है—तीखी, कच्ची और असुविधाजनक। यह मंदिर आधुनिक सजावटी अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता। यहां कोई मुलायम संगीत नहीं, कोई नियंत्रित शांति नहीं। यहां सत्य है—जैसा है, वैसा ही।

कालीघाट हमें सिखाता है कि शक्ति का सुंदर होना जरूरी नहीं। आस्था का आरामदेह होना भी अनिवार्य नहीं। देवी का मुस्कुराना तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। शायद मां काली कहती हैं—"मुझे समझने से पहले अपने डर से मिलो।" कामाख्या के बाद कालीघाट की यात्रा यह स्पष्ट कर देती है कि यहां स्त्री-देह का उत्सव नहीं, बल्कि शक्ति का साक्षात्कार है। यह साक्षात्कार डराता नहीं, बल्कि मुक्त करता है—उस क्षण में, जब हम अपने भीतर की असहज सच्चाइयों को स्वीकार करने का साहस कर पाते हैं।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

खुले आसमान, समुद्र की लहरों और रंगों के संगम से सूरत को मिलेगी नई पहचान, डुमस बीच पर उतरेगा 'डुमस आर्ट फेस्टिवल–2026'

(जीएनएस)। सूरत। कला जब दीवारों और गैलरियों से निकलकर खुले आकाश के नीचे सांस लेने लगे, तब उसका प्रभाव कहीं अधिक गहरा और जीवंत हो जाता है। कुछ ऐसा ही अनुभव सूरतवासियों को मिलने जा रहा है, जब 21 और 22 फरवरी 2026 को डुमस के लंगर समुद्र तट पर दो दिवसीय 'डुमस आर्ट फेस्टिवल–2026' का भव्य आयोजन किया जाएगा। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आर्ट एंड कल्चर कमेटी द्वारा आयोजित यह उत्सव केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि कला, प्रकृति और समाज के बीच संवाद स्थापित करने का एक सशक्त प्रयास है। समुद्र की लहरों की आवाज, रेत पर चलते कदमों के निशान और खुले आकाश के नीचे सजी कलाकृतियां—यह फेस्टिवल कला को आम लोगों के जीवन के और करीब लाने का माध्यम बनेगा। चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी के अनुसार, इस आयोजन का मूल उद्देश्य कलाकारों को एक ऐसा मंच देना है, जहां वे बिना किसी औपचारिक बंधन के अपनी रचनात्मकता को प्रस्तुत कर सकें और दर्शकों से सीधे जुड़ सकें। उनका कहना है कि बीच पर आयोजित यह फेस्टिवल न केवल कलाकारों को पहचान दिलाएगा, बल्कि सूरत को एक सांस्कृतिक और कलात्मक शहर के रूप में नई पहचान भी देगा।

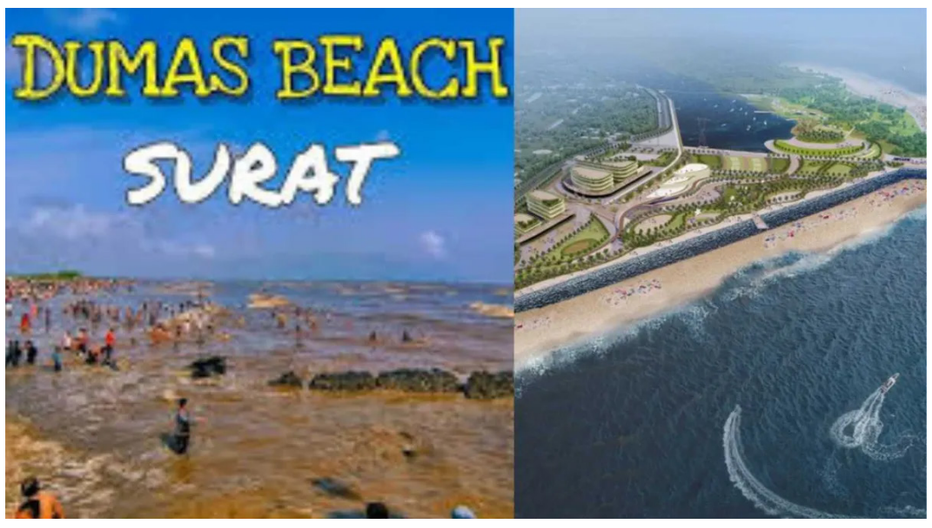

डुमस आर्ट फेस्टिवल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। इस समय-सारिणी को खास तौर पर इस तरह रखा गया है, ताकि लोग समुद्र तट की प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ कला का आनंद भी आराम से ले सकें। सुबह की नरम धूप और शाम के सुनहरे सूर्यास्त के बीच सजी कलाकृतियां दर्शकों के लिए एक अलग ही अनुभूति लेकर आएंगी।

फेस्टिवल में कला की लगभग हर विधा को शामिल किया गया है। पेंटिंग के विभिन्न रूपों से लेकर स्कल्पचर, स्केचिंग और ड्रॉइंग, कैलिग्राफी, डिजिटल आर्ट और फोटोग्राफी तक, हर तरह की रचनात्मक अभिव्यक्ति यहां देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंस्टॉलेशन आर्ट, क्राफ्ट और हैंडमेड आर्ट, क्ले और पॉटरी आर्ट, फैब्रिक और टेक्सटाइल आर्ट, ग्लास आर्ट, वुड आर्ट, मेटल आर्ट और मिक्स्ड मीडिया जैसी विधाएं इस उत्सव को और भी समृद्ध बनाएंगी। कला प्रेमियों के लिए यह किसी चलते-फिरते कला संग्रहालय से कम नहीं होगा।

इस फेस्टिवल की खास बात यह है कि यहां कला केवल देखने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसे महसूस करने और उसके निर्माण की प्रक्रिया को समझने का अवसर भी मिलेगा। कई स्टॉल्स पर लाइव आर्ट और परफॉर्मेंस आर्ट का आयोजन किया जाएगा, जहां कलाकार दर्शकों के सामने ही अपनी कृतियों को आकार देंगे। लाइव म्यूजिक, चाहे वह बैंड परफॉर्मेंस हो या सोलो इंस्ट्रूमेंटल, समुद्र तट के माहौल को और भी जीवंत बनाएगा। इसके साथ ही टैरो कार्ड रीडिंग आर्ट, मेडिटेशन और हीलिंग आर्ट जैसी गतिविधियां दर्शकों को मानसिक शांति और आत्मिक अनुभव से जोड़ेंगी।

आयोजकों का मानना है कि डुमस आर्ट फेस्टिवल हर उम्र के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। बच्चे रंगों और आकृतियों से जुड़ेंगे, युवा अपनी रचनात्मक ऊर्जा को पहचानेंगे और बुजुर्ग कला के माध्यम से स्मृतियों और संवेदनाओं से जुड़ाव महसूस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कलाकार और कला प्रेमी यहां सीधे संवाद कर सकेंगे, जिससे कला केवल प्रदर्शनी की वस्तु न रहकर एक जीवंत संवाद का रूप ले लेगी।

सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लंबे समय से आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत है। इस तरह के आयोजन लोकल और नेशनल लेवल के कलाकारों को प्रोत्साहन देते हैं और उन्हें अपने हुनर को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करते हैं। डुमस आर्ट फेस्टिवल इसी सोच का विस्तार है, जहां सूरत न केवल व्यापार और उद्योग के शहर के रूप में, बल्कि कला और संस्कृति के केंद्र के रूप में भी उभरता नजर आएगा।

आयोजकों के अनुसार, यह फेस्टिवल सूरत के लिए एक नई आर्टिस्टिक पहचान गढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। शहरवासियों के लिए यह परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने, समुद्र तट की खूबसूरती का आनंद लेने और कला के रंगों में डूबने का एक अनोखा अवसर होगा। डुमस आर्ट फेस्टिवल–2026 निश्चित रूप से सूरत के सांस्कृतिक कैलेंडर में एक यादगार अध्याय जोड़ने जा रहा है, जहां कला, प्रकृति और समाज एक-दूसरे से संवाद करते नजर आएंगे।

नौवीं बार बजट पेश करने की दहलीज पर निर्मला सीतारमण पीएम मोदी ने कहा—संसदीय इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की संसद एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार आम बजट पेश करने जा रही हैं और इसके साथ ही वह भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के लोकतांत्रिक और संसदीय इतिहास का गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि यह उपलब्धि केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि बदलते भारत और उसकी स्थिर आर्थिक दिशा का प्रतीक है।

संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पेश होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा पूरा हो चुका है और अब हम दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। उनके शब्दों में यह समय केवल एक और बजट पेश करने का नहीं, बल्कि देश के भविष्य की दिशा तय करने का है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आने वाले 25 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस सदी के दूसरे चरण का पहला बजट अब देश के सामने आने वाला है।

प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि संसद में लगातार नौ बार बजट पेश करना अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह न केवल वित्तीय निरंतरता और नीति-स्थिरता को दर्शाता है, बल्कि यह भी

दिखाता है कि देश की आर्थिक बागडोर एक अनुभवी और सशक्त नेतृत्व के हाथों में है। प्रधानमंत्री ने इसे महिलाओं की भूमिका और नेतृत्व क्षमता के लिए भी प्रेरणादायी उदाहरण बताया।

1 फरवरी को पेश होने वाला यह बजट मोदी सरकार का 15वां बजट होगा। साथ ही यह 2024 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद दूसरा पूर्ण बजट भी होगा। ऐसे में इस बजट को केवल वार्षिक आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि अगले कई वर्षों की आर्थिक दिशा और प्राथमिकताओं का रोडमैप माना जा रहा है। सरकार की नजर आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ-साथ वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर टिकी है। इस बजट के पीछे वित्त मंत्री के साथ एक अनुभवी और सशक्त टीम काम कर रही है, जिसमें प्रशासनिक अनुभव और आर्थिक विशेषज्ञता का संतुलन दिखाई देता है। आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर को बजट की पूरी रूपरेखा तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाला माना जा रहा है। वह बजट डिवीजन का नेतृत्व करती हैं, जो केंद्रीय बजट के मुख्य दस्तावेज तैयार करता है और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार की आर्थिक रणनीति को अंतिम रूप देता है। उनकी जिम्मेदारी केवल आंकड़ों को संतुलित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि संसाधनों के प्रभावी बंटवारे, सरकारी खर्च की सीमा तय करने और विकास व आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने की भी है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन की भूमिका भी इस बजट में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनका कार्यालय वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर करीबी नजर रखता है और अंतरराष्ट्रीय जोखिमों, भू-राजनीतिक तनावों तथा वैश्विक बाजारों के रुझानों का आकलन करता है। बजट से पहले उनके द्वारा किए गए आर्थिक विश्लेषण कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की स्थिति को समझने में मदद करते हैं। इसके साथ ही वे वित्त मंत्री को बड़े संरचनात्मक सुधारों, वित्तीय नीतियों और दीर्घकालिक आर्थिक योजना पर सलाह देते हैं, ताकि बजट केवल तात्कालिक जरूरतों तक सीमित न रहे, बल्कि भविष्य की मजबूत नींव भी रखे।

राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव के लिए यह बजट विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह उनके लिए राजस्व सचिव के रूप में पहला बजट होगा। उनके जिम्मे प्रत्यक्ष करों जैसे आयकर और कॉरपोरेट टैक्स के साथ-साथ अप्रत्यक्ष करों जैसे जीएसटी और सीमा शुल्क की निगरानी है। सरकार की कोशिश राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाए रखने की है, ताकि करदाताओं पर अनावश्यक बोझ न पड़े और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह भी संकेत दिया कि आने वाला बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं होगा, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और समावेशी विकास की सोच को आगे बढ़ाने वाला होगा। उन्होंने कहा कि देश आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां नीति-निर्णय और आर्थिक दिशा का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। ऐसे में बजट का महत्व और भी बढ़ जाता है।

लगातार नौवीं बार बजट पेश करने जा रहीं निर्मला सीतारमण का कार्यकाल कई वैश्विक और घरेलू चुनौतियों से भरा रहा है। कोरोना महामारी, वैश्विक मंदी की आशंकाएं, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं और भू-राजनीतिक तनाव जैसे हालात के बीच उन्होंने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री के बयान में यह भरोसा भी झलकता है कि देश ने इन चुनौतियों से सीख लेते हुए आगे की राह तय की है। कुल मिलाकर, यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक आत्मविश्वास, नीतिगत निरंतरता और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक माना जा रहा है। संसद में जब निर्मला सीतारमण नौवीं बार बजट भाषण देने के लिए खड़ी होंगी, तो वह केवल आंकड़े नहीं पढ़ेंगी, बल्कि देश के संसदीय इतिहास में एक नया और गौरवपूर्ण अध्याय भी जोड़ेंगी।

झारखंड में पड़हा राजा सोमा मुंडा की हत्या: जमीन कारोबारियों की साजिश और पूर्व छात्र का बदला

(जीएनएस)। झारखंड के खूंटी जिले में 7 जनवरी 2026 को हुए चर्चित पड़हा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड ने राज्य के जनजातीय इलाकों में सनसनी मचा दी थी। सोमा मुंडा, जो स्थानीय जनजातीय पंचायत व्यवस्था के प्रमुख और कई गांवों में पारंपरिक मामलों के निर्णायक थे, की हत्या ने न केवल सामाजिक व्यवस्था को हिला कर रख दिया बल्कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस हत्या के पीछे की साजिश अब पुलिस जांच के बाद सामने आई है, जिसमें जमीन कारोबारी, पुराने विवाद और एक पूर्व छात्र की व्यक्तिगत नाराजगी शामिल है। पुलिस के अनुसार, इस मामले में कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पैदल मार्च के जरिए खूंटी थाना तक ले जाया गया, जहां मुख्य सड़क पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। लोग आरोपियों के फोटो और वीडियो बनाने लगे, जिससे इस घटना का सामाजिक और राजनीतिक असर स्पष्ट हो गया। पुलिस ने बताया कि मुख्य शूटर के रूप में पकड़ा गया 20 वर्षीय मारकुस संगा था।

मारकुस संगा और सोमा मुंडा का पुराना स्कूल संबंध इस हत्या की मुख्य जड़ है। मारकुस कभी सोमा मुंडा के स्कूल का छात्र था, लेकिन 2022 में किसी कारणवश उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। पुलिस का कहना है कि इस बात से वह गुस्से में था, और जमीन कारोबार से जुड़े एक शख्स ने उसकी नाराजगी का फायदा उठाकर उसे पैसे और हथियार उपलब्ध कराए।

जांच में यह भी सामने आया कि खूंटी के हुटार चौक निवासी दानियल संगा और सोमा मुंडा के बीच लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था। करीब एक-दस साल पहले से 14 डिसमिल जमीन को लेकर दोनों के बीच तनातनी थी। पुलिस के अनुसार, जब भी दानियल उस जमीन पर निर्माण की कोशिश करता, सोमा मुंडा विरोध करते थे। इसी क्रम में 2025 के नवंबर-दिसंबर में जियरप्पा गांव में 32 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री की कोशिश भी सोमा मुंडा और ग्राम सभा के हस्तक्षेप से रुक गई थी, जिससे कथित तौर पर जमीन कारोबारियों में नाराजगी बढ़ गई।

7 जनवरी को सोमा मुंडा अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से खूंटी से अपने गांव लौट रहे थे। जमुआदाग तालाब के पास पहले से रेकी कर रहे आरोपियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। घटना के तुरंत बाद सोमा मुंडा की मौत हो गई। पुलिस ने मौके से एक देशी पिस्टल, चार गोलियां, पल्सर मोटरसाइकिल, एक कार, रेकी में इस्तेमाल बाइक, मोबाइल फोन, कपड़े और हेलमेट सहित कई अन्य वस्तुएं जब्त की हैं।

खूंटी के एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तारी और सबूतों की बरामदगी से हत्या के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि सोमा मुंडा सिर्फ एक पारंपरिक नेता ही नहीं थे, बल्कि जनजातीय समुदाय के सामाजिक और पारंपरिक मामलों में निर्णायक भूमिका निभाते थे। उनकी हत्या ने क्षेत्र में गहरा आक्रोश और शोक फैलाया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सोमा मुंडा की हत्या केवल व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम नहीं है, बल्कि जमीन कारोबारियों और पुराने विवाद का नतीजा है। उनका मानना है कि सोमा मुंडा ने हमेशा न्याय और पारंपरिक व्यवस्था की रक्षा की, इसी वजह से उनके विरोधी उन्हें मारने के लिए साजिश रच बैठे।

पुलिस अब पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हत्या के पीछे और कौन-कौन शामिल थे। मारकुस संगा के अलावा अन्य पांच आरोपियों के नाम और उनके भूमिकाओं का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या मदद करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत ने मचाई सनसनी: इंस्टाग्राम पोस्ट और वायरल वीडियो ने बढ़ाया रहस्य

(जीएनएस)। जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में सनातन धर्म प्रचारक और मोटिवेशनल स्पीकर साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। 25 वर्षीय साध्वी प्रेम बाईसा अपनी सुरीली आवाज, कथा वाचन और सोशल मीडिया पर सक्रिय उपस्थिति के लिए जानी जाती थीं। उनके इंस्टाग्राम पर 6 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, जो उनके आध्यात्मिक और प्रेरणादायक संदेशों के नियमित दर्शक थे। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत बुधवार को हुई और इस घटना ने उनके फॉलोअर्स और भक्तों को गहरे सदमे में डाल दिया। लेकिन मामले को और जटिल बनाने वाला मोड़ आया उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से, मौत के लगभग चार घंटे बाद प्रकाशित एक पोस्ट। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि देश के कई संत-महात्माओं और जगतगुरु शंकराचार्य को अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया था, लेकिन प्रकृति ने शायद कुछ और ही मंजूर किया। इस पोस्ट के बाद उनके फॉलोअर्स के बीच सस्पेंस और चिंता बढ़ गई। कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि अगर साध्वी की मौत पहले ही हो चुकी थी, तो यह पोस्ट किसने प्रकाशित किया।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे वीडियो ने मामले की रहस्यपूर्ण स्थिति को और गंभीर बना दिया। जुलाई 2025 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साध्वी प्रेम बाईसा को अपने पिता महंत वीरमनाथ के गले लगते देखा गया। वीडियो को एडिट कर पेश किए जाने का आरोप है, जिससे साध्वी और उनके पिता के बीच खूबसूरत और भावनात्मक रिश्ते को गलत संदर्भ में पेश किया गया। साध्वी ने पहले भी स्पष्ट किया था कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति उनके पिता ही हैं और यह बस एक भावुक मिलन था। उन्होंने कहा था कि वायरल वीडियो का उद्देश्य उनके रिश्ते को बदनाम करना है।

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद स्थानीय

लोगों और उनके समर्थकों में भारी तनाव और आक्रोश देखने को मिला। आरती नगर स्थित उनके आश्रम के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई और पोस्टमार्टम कराने की मांग को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। शुरुआत में उनके पिता ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया था, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। लोगों ने वाहन को घेर लिया और पोस्टमार्टम की मांग को अड़ियल तरीके से रखा। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने भी इस मामले में सक्रियता दिखाई। आश्रम के आसपास सीसीटीवी फुटेज गायब होने की शिकायतें मिलीं, जिसे लेकर भी जांच की मांग उठी। जांच एजेंसियों ने कहा कि घटनास्थल पर सभी डिजिटल साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों का संरक्षण करना प्राथमिकता है, ताकि साध्वी की मौत के वास्तविक कारण का पता लगाया जा सके। साध्वी प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम पोस्ट और वायरल वीडियो ने यह सवाल उठाया है कि क्या उनकी मौत किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण हुई या फिर इसमें किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि शामिल थी। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स ने पोस्ट को शेड्यूल किया हुआ बताया, जबकि अन्य लोग इसे फर्जी आत्महत्या के रूप में पेश किए जाने की संभावना मान रहे हैं। इसके अलावा, वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहस को और तेज कर दिया है, जहां लोग वीडियो के एडिट होने और संदर्भ को बदलने के आरोप लगा रहे हैं।

साध्वी प्रेम बाईसा का योगदान केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और प्रेरक भी रहा। उनकी कथाओं, वाचन और वीडियोज ने लाखों लोगों को जीवन में सकारात्मकता और मानसिक शक्ति देने का काम किया। इसलिए उनके फॉलोअर्स और भक्त उनकी मौत के पीछे किसी भी संभावित साजिश या रहस्य को जानने की मांग कर रहे हैं।

स्थानीय प्रशासन ने कहा कि साध्वी की मौत की गहन जांच जारी है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं, जिसमें इंस्टाग्राम पोस्ट का तकनीकी सत्यापन, वायरल वीडियो का मूल स्रोत, आश्रम में घटनाक्रम की जांच और फॉलोअर्स की मिली-जुली जानकारी शामिल है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि यदि किसी भी स्तर पर अपराध या लापरवाही पाई जाती है, तो जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

साध्वी प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम पोस्ट और वायरल वीडियो ने एक गंभीर सामाजिक और नैतिक बहस भी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और डिजिटल पोस्ट के माध्यम से किसी व्यक्ति की छवि को बदलने या उसे बदनाम करने की घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री के प्रमाण और सत्यापन की अहमियत को उजागर करती है।

अंततः, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की वास्तविक वजह का खुलासा केवल पुलिस जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों की गहन पड़ताल के बाद ही संभव होगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और इंस्टाग्राम पोस्ट ने उनके फॉलोअर्स में चिंता और सस्पेंस बढ़ा दिया है, और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं कि उनके जीवन और मृत्यु से जुड़े सभी तथ्य सार्वजनिक किए जाएं।

DEXONA इंजेक्शन से लेकर डिजिटल डेथ नोट तक जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत, हर सवाल के पीछे नया शक

(जीएनएस)। राजस्थान के जोधपुर से सामने आई 25 वर्षीय साध्वी प्रेम बाईसा की मौत ने न सिर्फ आध्यात्मिक जगत बल्कि आम समाज को भी भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। अपनी सुरीली आवाज, भावपूर्ण कथा वाचन और युवाओं में खास लोकप्रियता के कारण पहचान बना चुकी साध्वी की अचानक मौत को पहले एक सामान्य चिकित्सकीय लापरवाही माना गया, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, यह मामला कई परतों वाला और कहीं अधिक जटिल होता जा रहा है। एक ओर डेक्सोना इंजेक्शन की भूमिका पर सवाल हैं, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर सामने आया 'डिजिटल डेथ नोट' और पिता-गुरु से जुड़ा पुराना वायरल वीडियो इस मौत को रहस्य और संदेह के घेरे में ले जा रहा है। बताया जा रहा है कि साध्वी प्रेम बाईसा पिछले दो दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रही थीं। वह जोधपुर स्थित साधना कुटीर आश्रम में ही थीं और वहीं एक कंपाउंडर को बुलाया गया। आरोप है कि कंपाउंडर ने उन्हें डेक्सोना इंजेक्शन लगाया। आमतौर पर यह इंजेक्शन सूजन या एलर्जी जैसी स्थितियों में दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिना पूरी जांच और डॉक्टर की निगरानी के

यह इंजेक्शन देना उचित था। इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद साध्वी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह बेसुध हो गईं और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आनन-फानन में उनके पिता और गुरु वीरमनाथ उन्हें जोधपुर के प्रज्ञा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल लाने से पहले ही मृत घोषित कर दिया। इस बिंदु पर पहला बड़ा सवाल यही उठा कि क्या एक सामान्य इंजेक्शन से इतनी कम उम्र की, सक्रिय और सामान्य तौर पर स्वस्थ साध्वी की मौत हो सकती है, या फिर इंजेक्शन में कोई घातक रिएक्शन या अन्य तत्व शामिल था।

मामला यहीं खत्म नहीं होता। साध्वी की मौत के साथ ही छह महीने पुराने एक वीडियो ने फिर से सोशल मीडिया और लोगों की चर्चाओं में जगह बना ली। 13 जुलाई 2025 को वायरल हुए इस वीडियो में साध्वी अपने कमरे में लेटी हुई नजर आती हैं और एक शख्स कमरे में प्रवेश करता है। वह उनके गाल सहलाता है और दोनों के बीच आलिंगन का दृश्य दिखाई देता है। जब सामने आया कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके पिता और गुरु वीरमनाथ हैं, तो समाज में तीखी प्रतिक्रिया हुई। कई लोगों ने इसे मर्यादा के खिलाफ बताया, तो कई ने इसे निजी जीवन में दखल करार दिया। हालांकि वीडियो की सच्चाई और संदर्भ को लेकर आज भी स्पष्टता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इस घटना के बाद साध्वी पर मानसिक दबाव बढ़ा। कहा जा रहा है कि इस बदनामी और लगातार उठते सवालों ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था और आश्रम के भीतर भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था।

इसी बीच एक और हैरान करने वाला पहलू सामने आया, जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। साध्वी की मौत शाम करीब 5:30 बजे हो चुकी थी, लेकिन रात 9:30 बजे उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक भावुक पोस्ट साझा की गई। इस पोस्ट में लिखा था कि वह इस दुनिया को अलविदा कह रही हैं और यदि यहां न्याय नहीं मिला तो ऊपर वाले के दरबार में जरूर मिलेगा। इस पोस्ट को लोग 'डिजिटल डेथ नोट' कह रहे हैं। सवाल सीधा और गंभीर है—अगर साध्वी की मौत पहले ही हो चुकी थी, तो यह पोस्ट किसने और क्यों किया। क्या किसी ने जानबूझकर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, या फिर यह पोस्ट पहले से शेड्यूल की गई थी। पुलिस अब इस पोस्ट की तकनीकी जांच कर रही है, जिसमें लॉग-इन टाइम, डिवाइस और आईपी एड्रेस जैसे पहलुओं को खंगाला जा रहा है। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा संदेह का घेरा साध्वी के पिता और गुरु वीरमनाथ के इर्द-गिर्द घूम रहा है। वह न केवल उनके अभिभावक थे, बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे। आश्रम की आंतरिक गतिविधियों, वायरल वीडियो और साध्वी की मानसिक स्थिति को देखते हुए पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या मौत से पहले पिता-पुत्री के बीच कोई विवाद हुआ था या किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा था। स्थानीय लोगों के बीच भी दबी जुबान में कई तरह की चर्चाएं हैं, हालांकि कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है।

फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और 'विशरा' सुरक्षित रखने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मौत का कारण जहरीला पदार्थ था, किसी दवा का घातक रिएक्शन था या कुछ और। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे किसी भी संभावना को खारिज नहीं कर रहे हैं और मेडिकल लापरवाही, आत्महत्या के लिए उकसाना या हत्या—हर एंगल से जांच की जा रही है। साध्वी प्रेम बाईसा के सोशल मीडिया पर लाखों अनुयायी हैं। इंस्टाग्राम पर उन्हें सात लाख से अधिक लोग फॉलो करते हैं और यूट्यूब पर भी उनके हजारों प्रशंसक हैं। उनकी मौत के बाद समर्थकों में गहरा आक्रोश और दुख है। सभी की एक ही मांग है—सच सामने आए और दोषियों को सजा मिले। यह महज एक युवती की मौत नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और नैतिकता से जुड़े कई सवालों की कहानी बन चुकी है।

योगी कैबिनेट ने अजित पवार के निधन पर जताया गहरा शोकः महाराष्ट्र को हुई अपूरणीय क्षति

(जीएनएस)। लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया और शोक प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट ने बताया कि 28 जनवरी को बारामती, महाराष्ट्र में हुई विमान दुर्घटना में अजित पवार सहित अन्य लोगों के निधन की खबर अत्यंत दुखद है और इससे महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक वैभव के महत्वपूर्ण स्तंभों को अपूरणीय क्षति पहुँची है।

कैबिनेट ने शोक प्रस्ताव में कहा कि अजित पवार का निधन न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि महाराष्ट्र की जनता और राजनीतिक समाज के लिए भी अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपने दीर्घ सार्वजनिक जीवन में हमेशा समाज के हर वर्ग के कल्याण और राज्य के विकास के लिए काम किया। विशेषकर गरीबों, वंचितों और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने के उनके प्रयास हमेशा याद रखे जाएंगे। उनके नेतृत्व और जनसेवा की प्रतिबद्धता ने महाराष्ट्र की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में स्थायी प्रभाव डाला।

बैठक में उपस्थित मंत्रियों ने साझा किया कि अजित पवार का असामयिक निधन केवल एक राजनीतिक नुकसान नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व का अभाव है जिन्होंने अपने कार्यकाल में विकास, सामाजिक न्याय और प्रशासनिक उत्कृष्टता के लिए अडिग प्रयास किए। कैबिनेट ने दिवंगत पुण्यात्माओं की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि अजित पवार ने महाराष्ट्र में न केवल राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि सामाजिक कल्याण और जनसंपर्क में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि पवार के असामयिक निधन से महाराष्ट्र की जनता के बीच एक शून्यता उत्पन्न हुई है, जिसे भर पाना संभव नहीं है। राज्य मंत्रियों ने इस मौके पर कहा कि अजित पवार के व्यक्तित्व की पहचान उनके निष्ठावान नेतृत्व, जनता के प्रति सेवा भाव और राज्य निर्माण में उनके सक्रिय योगदान से हुई। उनका यह योगदान भविष्य में महाराष्ट्र और भारत के राजनीतिक इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा।

पश्चिम रेलवे – रतलाम

टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और उन्नयन में सिविल कार्य

संख्या : **W/623/5/1/NIT.** दिनांक : 27.01.2026, मंडल रेल प्रबंधक/मंडल कार्यालय (कार्य–लेखाशाखा) पश्चिम रेलवे, रतलाम, के लिये "खुली निविदा" ई–निविदा के माध्यम से वेबसाईट : **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित करते हैं। विवरण इस प्रकार है। **ई–टेंडरिंग :** RTM-2025-26-183, **कार्य का नाम :** रतलाम – डीआरएम कार्यालय परिसर में एमपीएलएस एनओसी के साथ टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, उन्नयन और टेलीकॉम गियर्स को बदलकर विश्वसनीयता सुधार। **अनुमानित मात्रा :** निविदा सूची के अनुसार, **अनुमानित लागत :** ₹1,28,78,069.28/–, **बयाना राशि :** ₹2,14,400/–, **कार्य समापन अवधि :** 10 महीने, **इसी प्रकार के कार्य :** किसी भी भवन का निर्माण कार्य, **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि :** 27.01.2026, **निविदा खुलने की तिथि :** 20.02.2026, • विस्तृत निविदा सूचना, अहाता शर्तें एवं अन्य शर्तें वेबसाईट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है।

मंडल रेल प्रबंधक (कार्यलेखा) रतलाम

SNP-432 पश्चिम रेलवे, रतलाम मंडल

हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly

मौसम ने बदला मिज़ाज, दिल्ली से पहाड़ों तक बढ़ी ठंड की आहट, बारिश और बर्फबारी से जनजीवन होगा प्रभावित

(जीएनएस)। दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। जनवरी के अंतिम दिनों में जहां लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलती दिख रही थी, वहीं अब पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों के लिए बारिश, तेज आंधी, बिजली कड़कने और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले तीन से चार दिन मौसम के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इस दौरान न सिर्फ तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, बल्कि सर्द हवाओं के कारण ठंड का असर भी बढ़ जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर में मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 31 जनवरी और 1 फरवरी को शाम और रात के समय तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में बिजली कड़कने और तेज आंधी की भी चेतावनी दी गई है। 2 फरवरी को भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। आज राजधानी में आसमान में बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश की संभावना कम है। अधिकतम तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बारिश और पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण अगले कुछ दिनों में दिल्ली की ठंड और बढ़ सकती है। बारिश के साथ-साथ दिल्लीवासियों के लिए एक राहत की खबर यह भी है कि वायु प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार देखने को मिला है। हालांकि अभी भी कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार बना हुआ है, लेकिन पहले की तुलना में स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। अलीपुर में AQI 204, आनंद विहार में 295, अशोक विहार में 263, बवाना में 202, चांदनी चौक में 274, लोधी रोड में 128, मंदिर मार्ग में 139, मुंडका में 288, नरेला में 140, नेहरू नगर में 304 और आरके पुरम में 305 दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि बारिश के बाद प्रदूषण के स्तर में और सुधार हो

सकता है, जिससे लोगों को सांस लेने में कुछ राहत मिलेगी।

उत्तर प्रदेश में भी मौसम का असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, बरेली, मेरठ, आगरा, मथुरा सहित कई जिलों में कोहरे और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ने लगेगा और 2 फरवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। बारिश के साथ ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट आएगी और ठंड का असर और तेज होगा। खासतौर पर सुबह और रात के समय लोगों को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

बिहार में भी मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर चेतावनी जारी की है। 3 फरवरी को भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद सहित कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल दिन में हल्की धूप निकल सकती है, लेकिन नमी बढ़ने के कारण ठंड का एहसास बना रहेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी मौसम बदला-बदला नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने आज तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ेगा। वहीं मध्य प्रदेश में पहले से हुई बारिश के कारण मौसम पहले ही ठंडा बना हुआ है और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है।

पंजाब और हरियाणा के साथ-साथ चंडीगढ़ में भी मौसम विभाग ने 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच बारिश और आसपास के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। किसानों को मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बारिश से फसलों पर भी असर पड़ सकता है।

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में गुरुवार को बर्फबारी दर्ज की गई थी, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो गई हैं और जनजीवन प्रभावित हुआ है। 31 जनवरी को एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

जम्मू-कश्मीर में भी 1 फरवरी को बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है। घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने से तापमान शून्य से नीचे जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले कुछ दिनों तक मौसम में अस्थिरता बनी रहेगी, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बदलाव सर्दियों के आखिरी चरण का संकेत है, जब पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी होती है। इससे एक ओर जहां किसानों को रबी फसलों के लिए कुछ हद तक फायदा मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर ठंड और मौसम की मार से आम जनजीवन प्रभावित होने की आशंका भी है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम अपडेट पर नजर रखें, ठंड से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाएं और यात्रा से पहले मौसम की स्थिति की जानकारी जरूर लें।

कुल मिलाकर, अगले कुछ दिन उत्तर भारत के लिए मौसम के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं। दिल्ली-एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार, राजस्थान और पहाड़ी राज्यों तक बारिश, ठंडी हवाएं और बर्फबारी ठंड को और तेज कर देंगी। ऐसे में सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।

राजस्थान में शराब दुकानों का समय बढ़ने का प्रस्ताव: रात 10 बजे तक खुलने की संभावना, राजनीतिक विरोध तेज

(जीएनएस)। राजस्थान में आबकारी और मद्य नीति में बदलाव की तैयारी ने राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज कर दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी आबकारी नीति में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया है कि अब आबकारी आयुक्त शराब दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव करने की शक्ति रखेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य की शराब दुकानों का संचालन अब रात 10 बजे तक किया जा सकेगा। इस कदम का उद्देश्य लाइसेंसियों को राहत देना, दुकानों का नवीनीकरण सुनिश्चित करना और मार्जिन बढ़ाना बताया जा रहा है, ताकि कारोबार सुचारू रूप से चले। वहीं इस प्रस्ताव ने सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर विवाद को जन्म दिया है और जनता तथा विपक्ष के बीच इसे लेकर तीखी बहस शुरू हो गई है।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए इसे जनविरोधी और चिंताजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 17 साल पहले शराब दुकानों के खुलने का समय रात 11 बजे से घटाकर रात

8 बजे तक सीमित किया था। उनका कहना है कि देर रात तक शराब की बिक्री सीधे तौर पर अपराध और महिलाओं के खिलाफ असुरक्षा को बढ़ावा देती है। अशोक गहलोत ने चेताया कि नैतिकता और सामाजिक सरोकारों को ताक पर रखकर लिए जाने वाले ऐसे फैसले राज्य की सामाजिक शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों के खुलने का समय बढ़ाने का प्रस्ताव समाज के लिए लाभकारी नहीं है और इसे रोकने की आवश्यकता है। गहलोत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार को इस मुद्दे पर जनभावनाओं और सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

सदन में कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने भी शराब नीति में इस बदलाव का विरोध किया और इसे निंदनीय करार दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में कई शराब की दुकानें ऐसी हैं, जिनमें बारकोड आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से रात 10 से 11 बजे तक शराब की बिक्री की जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के कारण सामाजिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दे उत्पन्न होते हैं। उनका कहना था कि वे इस प्रस्ताव का सदन में विरोध करेंगे और जनता की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए इसे रोकने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में इस नीति संशोधन को लेकर सामाजिक स्तर पर भी चिंता व्यक्त की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि देर रात तक शराब की बिक्री अपराध और महिलाओं के खिलाफ असुरक्षा को बढ़ावा देती है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों की राय यह है कि शराब की दुकानों का संचालन रात में बढ़ाने से स्थानीय सुरक्षा और सामाजिक माहौल प्रभावित हो सकता है। वहीं सरकार का तर्क यह है कि शराब की दुकानों का समय बढ़ाने से लाइसेंस धारकों को आर्थिक लाभ मिलेगा और व्यवसाय सुचारू रूप से चल सकेगा। इसके अलावा, सरकार का यह भी कहना है कि आबकारी आयुक्त के पास समय में बदलाव करने का अधिकार होने से आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन में लचीलापन बनेगा।

राजस्थान में यह मुद्दा न केवल आबकारी नीति तक सीमित है, बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर भी इसे लेकर बहस तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि शराब दुकानों का समय बढ़ाना सीधे तौर पर सामाजिक सुरक्षा और नैतिकता के खिलाफ है। वहीं सरकार का कहना है कि यह कदम व्यावसायिक हित और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इस विवाद ने जनता के बीच भी बहस को जन्म दिया है कि क्या देर रात तक शराब की बिक्री समाज के लिए हानिकारक हो सकती है या इसे आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक कदम माना जाना चाहिए। राजस्थान में आबकारी नीति का यह संशोधन लागू होगा या नहीं, यह निर्णय आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होगा।

कोकिंग कोल को रणनीतिक खनिज घोषित, भारत का इस्पात उद्योग मिलेगा मजबूती, आयात पर निर्भरता घटेगी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत ने गुरुवार को कोकिंग कोयले को 'क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल' घोषित कर एक ऐतिहासिक और रणनीतिक फैसला किया है। यह निर्णय घरेलू इस्पात उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, आयात पर अत्यधिक निर्भरता घटाने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय के अनुसार, यह कदम माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 के तहत लिया गया है और इसके बाद कोकिंग कोल को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की सूची में शामिल किया गया है। इस नए वर्गीकरण के चलते कोकिंग कोल के खनन और व्यापार से जुड़े अनुमोदन और प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी, अन्वेषण और खनन कार्यों में सुधार होगा और इस्पात उद्योग की आवश्यकताओं की आपूर्ति को समय पर सुनिश्चित किया जा सकेगा।

भारत में कोकिंग कोल के अनुमानित भंडार लगभग 37.37 अरब टन हैं, जो मुख्यतः झारखंड राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। बावजूद इसके, देश के इस्पात उद्योग की कोकिंग कोल की लगभग 95 प्रतिशत आवश्यकता आयात से पूरी होती रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में कोकिंग कोल का आयात 51.20 मिलियन टन था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 57.58 मिलियन टन हो गया। यह आयात न केवल देश की विदेशी मुद्रा पर दबाव डालता रहा है, बल्कि घरेलू उत्पादन और संसाधनों के इष्टतम उपयोग की संभावनाओं को सीमित करता था। कोयला मंत्रालय ने बताया कि कोकिंग कोल को रणनीतिक खनिज घोषित करने से अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आएगी और अन्वेषण तथा खनन कार्यों में सुधार होगा। यह निर्णय न केवल खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करेगा। इस वर्गीकरण से जुड़े कानूनी और वित्तीय प्रावधानों के अनुसार रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम और अन्य कानूनी भुगतान संबंधित राज्य सरकारों को प्राप्त होते रहेंगे। इससे राज्य और केंद्र दोनों को लाभ होगा और खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और संचालन की सुगमता बढ़ेगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। घरेलू कोकिंग कोल संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जाएगा, खनन क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाई जाएगी और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। घरेलू उत्पादन बढ़ने से न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि भारत का इस्पात उद्योग मजबूत होगा और यह देश के आत्मनिर्भर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहायक होगा। इस निर्णय को 'विकसित भारत 2047' के विज़न की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कोकिंग कोल को रणनीतिक खनिज घोषित करने का यह निर्णय इस्पात, निर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों में दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करेगा। इससे उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य तथा केंद्र सरकारों के राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही, यह कदम खनिज संसाधनों के सुरक्षित और व्यवस्थित उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में बाधा नहीं आएगी और उद्योग अपने उत्पादन लक्ष्य को समय पर पूरा कर सकेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने से देश की विदेशी मुद्रा बचत होगी और घरेलू उद्योगों की लागत घटेगी। इस निर्णय से कोयला और इस्पात क्षेत्रों में निजी निवेशकों की रुचि बढ़ेगी, जिससे तकनीकी विकास, आधुनिक प्रबंधन प्रणाली और खनन तथा शोधन में नवाचार को अपनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, घरेलू कोकिंग कोल के व्यापक उपयोग से राष्ट्रीय खनिज सुरक्षा सुनिश्चित होगी और देश का औद्योगिक ढांचा अधिक आत्मनिर्भर बनेगा।

मंत्रालय का कहना है कि इस निर्णय का लाभ केवल औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं रहेगा। इससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, नई प्रौद्योगिकियों के प्रशिक्षण और कार्यशाला की संभावनाएं बढ़ेंगी, और स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम भारत की आर्थिक रणनीति, औद्योगिक सुरक्षा और राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता को मजबूती देने के साथ-साथ देश के इस्पात उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती प्रदान करेगा।

डॉलर की मजबूती के दबाव में रुका नहीं रुपया, 91.95 पर बंद, वैश्विक संकेतों से प्रभावित बाजार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वैश्विक वित्तीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की लगातार मजबूती के बीच गुरुवार को भारतीय रुपये ने भी दबाव महसूस किया। दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद रुपया 91.95 प्रति डॉलर (अनंतिम) पर बंद हुआ, हालांकि कारोबार के दौरान यह 92 रुपये प्रति डॉलर के स्तर तक भी फिसल गया। इस कमजोरी का मुख्य कारण अमेरिका में आर्थिक संकेतक और फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति से जुड़े निर्णय माने जा रहे हैं, जिन्होंने डॉलर को वैश्विक स्तर पर मजबूत बना दिया है।

इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में गुरुवार की शुरुआत कमजोर रही। शुरुआती सौदों में रुपया 21 पैसे टूटकर 92 के स्तर पर चला गया। दिन के मध्य में कुछ राहत के संकेत तब आए जब शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ी, जिससे डॉलर की थोड़ी आवक हुई और रुपये ने 91.82 तक रिकवरी की। लेकिन कारोबार के दूसरे सत्र में डॉलर की मांग फिर से बढ़ने लगी और रुपये पर दबाव लौट आया। इस तरह दिन का अंत 91.95 प्रति डॉलर पर हुआ, जो दिनभर के उतार-चढ़ाव का संकेत देता है।

अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले रुपये की चाल मिली-जुली रही। ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले रुपये में कमजोरी देखी गई और यह 37.69 पैसे टूटकर 126.93 पर बंद हुआ। वहीं यूरो के मुकाबले भारतीय मुद्रा ने मजबूती दिखाई और 8.59 पैसे की बढ़त के साथ 109.94 पर समाप्त हुई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस मिश्रित स्थिति का कारण वैश्विक संकेतक और अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट व तेल बाजारों की स्थिति दोनों हैं।

विशेषज्ञ रवि चंदर खुराना के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा हाल ही में ब्याज दरों में कटौती न करने का निर्णय, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और डॉलर इंडेक्स में सुधार लेकर आया है। इस परिस्थिति ने डॉलर को अन्य वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले मजबूती दी। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने भी डॉलर की मांग बढ़ाई, जिससे रुपये पर दबाव बना। तेल की बढ़ती कीमतों का असर सीधे भारतीय आयातक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि रुपये की अस्थिरता आगामी सप्ताह में भी जारी रह सकती है। वैश्विक संकेतक, तेल और कच्चे माल की कीमतें, साथ ही अमेरिका और यूरोप के वित्तीय निर्णय रुपये की चाल को प्रभावित करेंगे। विदेशी निवेशकों की सक्रियता और शेयर बाजार की प्रवृत्ति भी रुपये के उतार-चढ़ाव में अहम भूमिका निभा सकती है।

इस दौरान भारतीय उद्योग जगत और वित्तीय संस्थानों के लिए भी यह स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। निर्यातक डॉलर की मजबूती को लाभ में बदल सकते हैं, लेकिन आयातक उच्च लागत का सामना करेंगे। वहीं विदेशी पूंजी निवेश की प्रवृत्ति और डॉलर की मजबूती से बैंकिंग और क्रेडिट बाजारों में अस्थिरता बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

गौरतलब है कि रुपये की कमजोरी सीधे आम आदमी और कारोबारी वर्ग को प्रभावित कर सकती है। डॉलर आधारित लेनदेन और आयातित वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस स्थिति में विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों को सावधानीपूर्वक बाजार की चाल पर नजर रखनी होगी, जबकि केंद्र और रिजर्व बैंक को मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

इस तरह गुरुवार का विदेशी मुद्रा बाजार दर्शाता है कि अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मजबूती और अंतरराष्ट्रीय तेल व कच्चे माल की कीमतें भारतीय रुपये के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। आने वाले दिनों में वैश्विक संकेतक और घरेलू आर्थिक गतिविधियां ही रुपये की दिशा तय करेंगी, जबकि कारोबारियों और निवेशकों को अनिश्चितता के बीच संतुलित रणनीति अपनाने की जरूरत है।

माघ के अंतिम दिनों में जौनपुर में बढ़ी ठंड, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंचा, स्वास्थ्य पर खतरे के संकेत

(जीएनएस)। जौनपुर। जिले में मौसम ने माघ के अंतिम दिनों में एक बार फिर करवट बदल दी है। गुरुवार को सुबह से घने बादल और ठंडी हवाओं ने गलन (शीतल प्रभाव) को और तेज कर दिया, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। लोगों को दिन की शुरुआत ही कंपकंपी के साथ करनी पड़ी और कई सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाते लोग नजर आए। बीते बुधवार को धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन शाम ढलते ही सर्दी ने फिर अपना असर दिखाया।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री तक पहुंच गया। आर्द्रता 89 प्रतिशत रही और हवा की गति लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक 124 रहा, जो स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य स्तर में माना जाता है। इसके मुकाबले बुधवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा था और आर्द्रता 79 प्रतिशत, वायु गुणवत्ता सूचकांक 131 रही। इस अचानक बदलाव का असर सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और खासकर संवेदनशील वर्ग के लिए खतरे के संकेत दे रहा है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार सुबह और शाम की तेज गलन से विशेष तौर पर हृदय रोगियों, मधुमेह और उच्च रक्तचाप से प्रभावित लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जिले के वरिष्ठ फिजिशियन एवं हृदय विशेषज्ञ डॉ. मनमोहन श्रीवास्तव ने बताया कि ठंड के कारण ब्लड प्रेशर में अचानक उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे लकवे (स्ट्रोक) का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ने से हार्ट अटैक की संभावना भी अधिक रहती है।

डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि इस मौसम में लोगों को बचाव के लिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। गुनगुना पानी पीना, नमक की मात्रा सीमित रखना और हल्का व्यायाम करना जरूरी है। उन्होंने बुजुर्गों और 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से अपील की है कि वे सुबह की ठंड में अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। साथ ही गुनगुने पानी से स्नान करना, संतुलित आहार लेना और तैलीय, वसा युक्त भोजन से परहेज करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा।

सोना वायदा में 9085 रुपये, चांदी वायदा में 19634 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा में 162 रुपये का ऊछाल

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 395568.09 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 148591.77 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 246952.95 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 50501 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 5429.15 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 127819.35 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 169882 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 180779 रुपये के ऑल टाइम हाई और नीचे में 169882 रुपये पर पहुंचकर, 165915 रुपये के पिछले बंद के सामने 9085 रुपये या 5.48 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 175000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 10774 रुपये या 7.7 फीसदी बढ़कर 150750 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 1326 रुपये या 7.55 फीसदी बढ़कर 18881 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी फरवरी वायदा 168000 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 182130 रुपये के ऑल टाइम हाई और नीचे में 168000 रुपये पर पहुंचकर, 9110 रुपये या 5.45 फीसदी बढ़कर 176202 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 175500 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 190018 रुपये के ऑल टाइम हाई और नीचे में 175500 रुपये पर पहुंचकर, 174329 रुपये के पिछले बंद के सामने 13872 रुपये या 7.96 फीसदी बढ़कर 188201 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 399000 रुपये के भाव पर खूलकर, 409800 रुपये के ऑल टाइम हाई और 395001 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 385366 रुपये के पिछले बंद के सामने 19634 रुपये या 5.09 फीसदी की तेजी के संग 405000 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 23961 रुपये या 6.12 फीसदी की तेजी के संग 415697 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 23901 रुपये या 6.1 फीसदी की मजबूती के साथ 415702

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 148591.77 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 246952.95 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 127819.35 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 50501 पॉइंट के स्तर पर

रुपये प्रति किलो बोला गया।

मेटल वर्ग में 15692.24 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 98.1 रुपये या 7.42 फीसदी की तेजी के संग 1419.8 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 12.5 रुपये या 3.74 फीसदी की तेजी के संग 346.9 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 15.4 रुपये या 4.65 फीसदी की मजबूती के साथ 346.85 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 4.3 रुपये या 2.19 फीसदी बढ़कर 200.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 4518.68 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5894 रुपये के भाव पर खूलकर, 6005 रुपये के दिन के उच्च और 5887 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 162 रुपये या 2.79 फीसदी की मजबूती के साथ 5964 रुपये प्रति बैरल बोला गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 163 रुपये या 2.81 फीसदी बढ़कर 5965 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 351 रुपये के भाव पर खूलकर, 363.3 रुपये के दिन के उच्च और 348 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 342.8 रुपये के पिछले बंद के सामने 10 रुपये या 2.92 फीसदी की तेजी के संग 352.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 10 रुपये या 2.92 फीसदी की तेजी के संग 353 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 1008.5 रुपये के भाव पर खूलकर, 4.9 रुपये या 0.49 फीसदी की गिरावट के साथ 987.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 90964.54 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 36854.81 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 13318.98 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 1092.42 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 160.70 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 1092.89 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 1186.43 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 3323.36 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 6.94 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 18749 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 111452 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 34154 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 511505 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 63880 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 14069 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 35283 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 99225 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 23278 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 18804 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 49024 पॉइंट पर खूलकर, 51880 के उच्च और 49024 के नीचले स्तर को छूकर, 2904 पॉइंट बढ़कर 50501 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 6000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 93.8 रुपये की बढ़त के साथ 305.9 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 7.4 रुपये की बढ़त के साथ 40.95 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 172000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 10597 रुपये की बढ़त के साथ 20931.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 365000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 12541 रुपये की बढ़त के साथ 63491 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1390 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 68.29 रुपये की बढ़त के साथ 91.51 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 345 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4.13 रुपये की बढ़त के साथ 6.49 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5900 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 76.2 रुपये की गिरावट के साथ 268.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 3.55 रुपये की गिरावट के साथ 36.95 रुपये हुआ। सोना फरवरी 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 1398.5 रुपये की गिरावट के साथ 3213.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 800.5 रुपये की गिरावट के साथ 6450 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 12.29 रुपये की गिरावट के साथ 21.24 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 285 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 14 पैसे के सुधार के साथ 0.49 रुपये हुआ।